



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2008/ज्येष्ठ 5, 1930

No. 84]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2008/JYAIJSTHA 5, 1930

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 26 मई, 2008

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(मध्यवर्ती) विनियम, 2008

सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538.—
बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) वे विभिन्न वर्गों के मध्यवर्तीयों के संबंध में ऐसी तारीखों को प्रवृत्त होंगे जैसा बोर्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु यह कि इन विनियमों के अध्याय V और VI के उपबंध राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "सहयुक्त" से मध्यवर्ती द्वारा, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, नियंत्रित कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति जो, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, मध्यवर्ती को नियंत्रित करता है, या ऐसे मध्यवर्ती के साथ सामान्य नियंत्रण के अधीन कोई सत्ता अथवा व्यक्ति, अभिप्रेत है, और जहाँ ऐसा मध्यवर्ती प्रकृत व्यक्ति है उसके अंतर्गत ऐसे मध्यवर्ती का कोई नातेदार आएगा और जहाँ ऐसा मध्यवर्ती नियमित निकाय है उसके अंतर्गत इसकी समूह कंपनियाँ (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) या उसकी किसी पुनः अधिनियमिति में यथा परिभाषित) या कंपनियाँ, जो उसी प्रबंध के अधीन हैं, आएंगी ;

(ग) "प्रमाणपत्र" से सुसंगत विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा मध्यवर्ती को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रास्थिति या गढ़न का परिवर्तन", मध्यवर्ती के संबंध में, के अंतर्गत निम्नलिखित है—

(i) समाप्तेन, अविलयन (डीमर्जर), समेकन या कम्पनी पुनर्संरचना का कोई अन्य प्रकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 391 के विस्तार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तत्स्थानी उपबंध के भीतर आने वाला, अथवा कोई करार या इंतजाम जिसका प्रभाव ऐसी कंपनी पुनर्संरचना का होगा;

(ii) मध्यवर्ती के नियंत्रण में काई परिवर्तन;

- (iii) मध्यवर्ती को विधिक हैसियत में कोई परिवर्तन;
- (ङ) "नियंत्रण", मध्यवर्ती के संबंध में, के अंतर्गत अलग-अलग या सामान्य मति से कार्य करते हुए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे मध्यवर्ती के प्रबंध या नीतिगत विनिश्चयों पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, नियंत्रण रखने की शक्ति होगी;
- (च) "प्ररूप" से अनुसूची 1 में प्ररूप अभिप्रेत है;
- (छ) "मध्यवर्ती" से अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) तथा (खक) और धारा 12 की उप-धारा (1) और (1क) में उल्लिखित व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 के संबंध में आस्ति प्रबंध कम्पनी, समाशोधन निगम या समाशोधन गृह का समाशोधन सदस्य और स्टॉक एक्सचेंज के व्युत्पन्नी खंड का व्यापारिक सदस्य सम्मिलित है किन्तु जिसमें विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता (निवेशक), विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता, पारस्परिक निधि, सामूहिक विनिधान (निवेश) स्कीम और जोखिम पूँजी निधि सम्मिलित नहीं है;
- (ज) "निरीक्षण प्राधिकारी" से विनियम 17 के उप-विनियम (1) के निवंधनों के अनुसार मध्यवर्ती की बहियों, लेखों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त एक या अधिक व्यक्ति अभिप्रेत है (हैं);
- (झ) "प्रधान अधिकारी" से वह कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो मध्यवर्ती के क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार है और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है -
- (i) स्वत्वधारी, सांपत्तिक समुद्धान के मामले में;
 - (ii) कोई भागीदार, भागीदारी फर्म के मामले में;
 - (iii) पूर्णकालिक/कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक, नियमित निकाय के मामले में;
 - (iv) न्यासी, न्यास के मामले में;
 - (v) कोई मूल कर्मचारी; और
 - (vi) सुसंगत विनियमों के अधीन प्रधान अधिकारी के रूप में पदाधिकारिता कोई व्यक्ति ;
- (ज) "सुसंगत विनियम" (या "सुसंगत विनियमों") से मध्यवर्तीयों के वर्ग के प्रति लागू बोर्ड द्वारा बनाए गए कोई विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ट) "प्रतिभूति विधि" (या "प्रतिभूति विधियाँ" या "प्रतिभूति विधियों") से अधिनियम, प्रतिभूति सेविदा (विनियम)

- अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) और तद्धीन बनाए गए नियम और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ठ) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ड) "स्व-विनियामक संगठन" से बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण रूप से मान्यताप्राप्त या के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्तीयों के वर्ग का संगठन अभिप्रेत है और जिसमें स्टॉक एक्सचेंज सम्मिलित है।
- (२) इन विनियमों में उपयोग किए गए और अपरिभाषित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम; या प्रतिभूति सेविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन उनके लिए नियत है।

अध्याय II

मध्यवर्तीयों का रजिस्ट्रीकरण

3. प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन .-(१) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, आवेदन, मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए, बोर्ड को अनुसूची 1 के प्ररूप के में ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो सुसंगत विनियमों के अधीन उपलब्ध कराये जाने के लिए अपेक्षित हो, और आवेदन फीस, जैसा सुसंगत विनियमों में विनिर्दिष्ट हो के साथ किया जाएगा :

परन्तु यह कि स्टॉक दलाल या उप-दलाल या व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य या निक्षेपागार सहभागी के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला आवेदक आवेदन ऐसी अतिरिक्त जानकारी के साथ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से या समाशोधन निगम के माध्यम से जिसका आवेदक सदस्य या व्यापारिक सदस्य है या निक्षेपागार के माध्यम से जिसमें आवेदक सहभागी के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव करता है, यथास्थिति, करेगा :

परन्तु यह और कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से ही, मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, जैसा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सुसंगत स्व-विनियामक संगठन को प्ररूप के में ऐसी अतिरिक्त जानकारी और आवेदन फीस के साथ किया जाएगा जैसा सुसंगत विनियमों में विनिर्दिष्ट हो।

(२) स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम, निक्षेपागार या विनिर्दिष्ट स्व-विनियामक संगठन, यथास्थिति, इन विनियमों, सुसंगत विनियमों, और संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम, निक्षेपागार या स्व-विनियामक संगठन के नियमों, विनियमों या उप-विधियों के निवंधनों के अनुसार आवेदक की पात्रता की परीक्षा करेंगे और बोर्ड

को आवेदन फीस के साथ आवेदन अपनी सिफारिश के साथ यथासंभव शीघ्र किन्तु विनिर्दिष्ट आवेदन फीस के साथ संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के अपश्चात् अप्रेक्षित करेंगे।

(3) उप-विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मध्यवर्ती के संबंध में इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व मध्यवर्ती द्वारा किया गया कोई आवेदन, जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ या जो उसके निकट की हों जो प्ररूप के में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट है जैसा सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो, जो बोर्ड के पास लाई जाए है, उप-विनियम (1) के अनुसरण में किए गए आवेदन के रूप में माना जाएगा और इसे तदनुसार निपटारा जाएगा।

(4) मध्यवर्ती, जिसे ऐसे मध्यवर्ती के संबंध में इन विनियमों के प्रारंभ के पूर्व सुसंगत विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, ऐसी हैसियत से कार्य करना जारी रख सकेगा, निम्नलिखित के अध्यधीन,-

(क) जहाँ प्रमाणपत्र विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए प्रदान किया गया था, उप-विनियम (1) के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन मध्यवर्ती द्वारा कम से कम ऐसी कालावधि की समाप्ति के तीन मास पूर्व या ऐसे मध्यवर्ती के संबंध में इन विनियमों के प्रारंभ से दो वर्षों की समाप्ति के तीन मास पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, किया जाएगा और यदि मध्यवर्ती ऐसा करने में असफल रहता है, तो यह ऊपर उल्लिखित कालावधि की समाप्ति से ही मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना छोड़ देगा;

(ख) जहाँ प्रमाणपत्र मध्यवर्ती को स्थायी आधार पर प्रदान किया गया हो, तो वहाँ प्रमाणपत्र इन विनियमों के अधीन इस शर्त के अध्यधीन विधिमान्य रह सकेगा कि मध्यवर्ती, ऐसे मध्यवर्ती के संबंध में इन विनियमों के प्रारंभ के दो वर्षों के भीतर, बोर्ड को प्ररूप करने के तीन मासों के भीतर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर डालेगा :

परंतु यह कि खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट समय बोर्ड द्वारा छह मास की कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा, मध्यवर्ती द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर।

(5) मध्यवर्ती जिसने उप-नियम (4) के खण्ड (ख) के उपबंधों का अनुपालन किया है, के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, सुसंगत विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान के अध्यधीन।

(6) सुसंगत विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, आवेदक या मध्यवर्ती यथास्थिति एक या अधिक मध्यवर्तीयों के क्रियाकलाप कर सकेगा केवल यदि यह प्रत्येक ऐसे क्रियाकलाप को करने के लिए पृथक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करता है।

4. जानकारी को प्रकट करना.—(1) प्ररूप के भाग I में अंतर्विष्ट जानकारी जनता के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर ऐसी जानकारी डालते हुए प्रकट की जाएगी :

परंतु यह कि प्ररूप के भाग II में मध्यवर्ती द्वारा दी गई अन्य सुसंगत जानकारी जो मध्यवर्ती के वाणिज्यिक विश्वास और निजी जानकारी से संबंधित है, बोर्ड द्वारा गोपनीय मानी जा सकेगी।

(2) इन विनियमों के अधीन दी गई या डाली गई जानकारी में किसी तात्त्विक परिवर्तन को मध्यवर्ती द्वारा तत्परता से अद्यतन बनाया जाएगा किन्तु ऐसे परिवर्तन के होने के पंद्रह दिनों के अपश्चात् ।

5. जानकारी और स्पष्टीकरण देना.—(1) बोर्ड आवेदक से अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा, ऐसे मध्यवर्ती के क्रियाकलाप से सुसंगत मामले के संबंध में या जो बोर्ड द्वारा अन्यथा आवश्यक समझा जाए, आवेदन पर विचार करने और उसका निपटारा करने के लिए।

(2) आवेदक बोर्ड के समाधानप्रद रूप में ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण, बोर्ड द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा।

6. जानकारी का सत्यापन.—(1) आवेदन, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी और इसकी पात्रता पर विचार करते समय, बोर्ड, यदि यह ऐसी वांछा करता है, तो दस्तावेजों, कार्यालय स्थान की अस्तित्व जांच द्वारा जानकारी का सत्यापन कर सकेगा, और कार्यालय स्थान, अवसरंचना तथा प्रौद्योगिक समर्थन जो आवेदक के पास होना अपेक्षित है की उपलब्धता का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रयोजन के लिए, बोर्ड कोई व्यक्ति जिसमें लेखापरीक्षक सम्मिलित है नियुक्त कर सकेगा।

7. आवेदन पर विचार.—(1) आवेदक की पात्रता और ऐसे आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करने के लिए, बोर्ड उन सभी मामलों पर विचार करेगा जो यह प्रतिभूति बाजार में क्रियाकलापों से सुसंगत समझता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं किन्तु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं—

(क) क्या आवेदक या इसके सहयुक्तों में से किसी को पहले कभी बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र से इंकार किया गया है और यदि हों, तो ऐसे इंकार का आधार;

(ख) क्या आवेदक, इसके निदेशक या भागीदार, या न्यासी, यथास्थिति, या इसका प्रधान अधिकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी तर्कित मुकदमें में अंतर्विलित है जिसका आवेदक के कारबार या प्रतिभूति बाजारों के विकास या इनकी कार्यप्रणाली से प्रतिकूल संबंध हो;

(ग) क्या आवेदक पात्रता मानदण्ड और अन्य अपेक्षाओं, इन विनियमों और सुसंगत विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट, को पूरा करता है;

(घ) क्या आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करना विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित और प्रतिभूति बाजार के विकास में है।

- (2) प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कोई आवेदन :
- (क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और प्ररूप क में अपेक्षाओं और सुसंगत विनियम में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;
- (ख) जिसमें ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट नहीं है जो बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो;
- (ग) जो गलत, मिथ्या या भ्रामक स्वरूप का है;
- (घ) जहां आवेदक इन विनियमों या सुसंगत विनियमों के अधीन यथा उपर्याप्ति पात्रता अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं है;
- (ड.) जहां आवेदक अनुसूची II में यथा कथित 'उपयुक्त तथा उचित स्वरूप' नहीं है;
- (च) जहां प्रधान अधिकारी के पास अपेक्षित अहता या अनुभव, सुसंगत विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित, नहीं है;

बोर्ड द्वारा ऐसे कारणों से जो बोर्ड द्वारा लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे नामंजूर किया जाएगा ।

(3) आवेदन नामंजूर करने से पूर्व, आवेदक को, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, इस प्रयोजन के लिए, कमियों की पूर्ति करने के लिए लिखित रूप में अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह कि जहां आवेदन इस कारण से नामंजूर किया जाता है कि इसमें मिथ्या या भ्रामक जानकारी अंतर्विष्ट है, तो वहां कोई ऐसा अवसर नहीं दिया जा सकेगा और आवेदक ऐसी नामंजूरी की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए इन विनियमों या किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कोई आवेदन नहीं करेगा ।

8. प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया.—(1) बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक पात्र है, सुसंगत विनियमों में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और इस संबंध में आवेदक को सूचना भेजेगा :

परंतु यह कि जहां बोर्ड या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण (अधिकरण) के समक्ष लंबित कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण हो सकेगा, तो वहां बोर्ड सशर्त रजिस्ट्रीकरण देगा ।

(2) जब मध्यवर्ती, जिसे प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो और जिसने प्ररूप के दाखिल किया हो, इन विनियमों के अधीन, नया क्रियाकलाप प्रारंभ करना चाहता है जिसके लिए सुसंगत विनियमों के अधीन पृथक प्रमाणपत्र अपेक्षित है, तब इससे, ऐसा प्रमाणपत्र चाहते समय, प्ररूप के दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा, और यह बोर्ड को केवल ऐसी अतिरिक्त जानकारी देगा जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित है ।

9. प्रमाणपत्र की शर्तें.—(1) बोर्ड द्वारा मध्यवर्ती को प्रदान किया गया कोई प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्—

(क) जहां मध्यवर्ती अपनी प्रासिति या गठन को परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है, तो यह प्रासिति या गठन में ऐसे परिवर्तन के पश्चात् मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा;

(ख) यह सुसंगत विनियमों के अनुसार लागू फीस का भुगतान करेगा;

(ग) यह प्रतिभूति विधियों के उपबंधों और निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों जो तद्धीन जारी किए जाएं का पालन करेगा;

(घ) यह विनियम 4 की अपेक्षाओं का सतत रूप से अनुपालन करेगा;

(ड.) यह पात्रता मानदंड और अन्य अपेक्षाओं, इन विनियमों और सुसंगत विनियमों में विनिर्दिष्ट, को पूरा करेगा :

परंतु यह कि बोर्ड अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो यह विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित या प्रतिभूति बाजार के सुव्यवस्थित विकास में या मध्यवर्ती के कामकाज के विनियमन के लिए ठीक समझे और मध्यवर्ती ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा ।

(2) पूर्व अनुमोदन के लिए निवेदन, उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन, जो सभी प्रकार से पूर्ण है का निपटारा बोर्ड द्वारा ऐसे निवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों की कालावधि के भीतर किया जाएगा और जहां बोर्ड के विनिश्चय की सूचना मध्यवर्ती को उक्त साठ दिनों की कालावधि के भीतर न दी गयी हो, तो वहां पूर्व अनुमोदन प्रदान किया गया समझा जाएगा ।

(3) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन पूर्व अनुमोदन के लिए निवेदन में, प्रासिति या गठन में प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् मध्यवर्ती के बाबत प्ररूप क में जानकारी अंतर्विष्ट होगी और प्ररूप के भाग 1 के अधीन जानकारी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर डाली जाएगी ।

10. प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार या प्रमाणपत्र की समाप्ति का प्रभाव.—(1) जहां मध्यवर्ती विनियम 3 के उप-विनियम (4) के अधीन आवेदन करने में असफल हुआ हो या जहां विद्यमान मध्यवर्ती को इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार किया गया हो, तो वहां मध्यवर्ती:

(क) तुरंत ऐसे मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना छोड़ देगा;

(ख) अपने क्रियाकलाप ऐसे दूसरे मध्यवर्ती को अंतरित करेगा जिसे ऐसा क्रियाकलाप करने के लिए प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो और अपने ग्राहकों या विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को अपनी अभिरक्षा में धारित उनकी प्रतिभूतियों या निधियों को, ऐसे ग्राहक या विनिधानकर्ता के प्रति किसी अतिरिक्त लागत के बिना, वापस लेने या अंतरित करने के लिए अनुशास देगा;

(ग) मध्यवर्ती द्वारा उपगत या ग्रहण किए गए दायित्व के विषय में व्यवस्थाएं करेगा;

(घ) ऐसी अन्य कार्यवाई करेगा, ऐसी समय कालावधि के भीतर और रीति में, जैसा सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित किया जाए या जैसा बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए।

(2) मध्यवर्ती को इन विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र प्रदान करने से इंकार करते समय, बोर्ड मध्यवर्ती पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसा यह मध्यवर्ती के विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) या ग्राहकों के संरक्षण या प्रतिभूति बाजार के लिए ठीक समझता है और ऐसी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

11. प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि.—
अधिनियम, इन विनियमों और सुसंगत विनियमों के उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन, मध्यवर्ती को प्रदान किया गया प्रमाणपत्र स्थायी होगा जब तक कि इन विनियमों के अनुसार मध्यवर्ती द्वारा अध्यर्पित न कर दिया जाए या निर्लिखित या रद्द न कर दिया जाए।

अध्याय-III

मध्यवर्तीयों की साधारण बाध्यताएँ

12. साधारण बाध्यताएँ.—(1) मध्यवर्ती बोर्ड को अपने अनुपालन अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को निर्मलिखित प्रमाणित करते हुए उपलब्ध करायेगा :

(क) मध्यवर्ती द्वारा इन विनियमों और सुसंगत विनियमों के अधीन सतत आधार पर सभी बाध्यताओं, जिम्मेदारियों और पात्रता मानदंड की पूर्ति का अनुपालन ;

(ख) कि प्ररूप के में और सुसंगत विनियमों के अधीन किए गए सभी प्रकटीकरण सही और संपूर्ण हैं।

(2) प्रत्येक मध्यवर्ती अपने सभी कार्यालयों जिनमें शाखा कार्यालय सम्मिलित हैं में प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(3) मध्यवर्ती उस अनुपालन अधिकारी का नाम और उसके संपर्क संबंधी ब्लौरे भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा जिसको किसी विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायत की दशा में शिकायत की जा सकेगी।

(4) मध्यवर्ती ऐसी बहियां, लेखें और अभिलेख रखेगा जैसा सुसंगत विनियमों में विनिर्दिष्ट हो।

13. विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों को दूर करना.—
(1) मध्यवर्ती विनिधानकर्ता शिकायतों को तत्परता से दूर करने के लिए प्रयास करेगा किन्तु उसकी प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के अपश्चात् और जब बोर्ड द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए यह बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करेगा।

(2) मध्यवर्ती इसके द्वारा प्राप्त विनिधानकर्ता शिकायतों और ऐसी शिकायतों को दूर करने के संबंध में अभिलेख रखेगा।

(3) मध्यवर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्राप्त, दूर की गई विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों की संख्या और मध्यवर्ती द्वारा उनकी प्राप्ति के तीन मास से अधिक तक दूर न की गई शेष विनिधानकर्ता शिकायतों से संबंधित जानकारी बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर डालेगा।

14. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति.—(1) मध्यवर्ती बोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए या जारी अधिनियम, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिपत्रों और आदेशों, अथवा संबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों, या स्व-विनियामक संगठन के नियमों, विनियमों और उप-विधियों, जहां लागू हों, की अपेक्षाओं के इसके द्वारा अनुपालन का अनुश्रवण करने के लिए अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगा :

परंतु यह कि मध्यवर्ती अनुपालन अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकेगा यदि यह मध्यवर्ती का क्रियाकलाप नहीं कर रहा है।

(2) अनुपालन अधिकारी मध्यवर्ती द्वारा किसी तात्त्विक अननुपालन कि रिपोर्ट, लिखित रूप में, मध्यवर्ती या इसके निदेशक बोर्ड को देगा।

15. विनिधान सलाह.—(1) मध्यवर्ती, इसके निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी या मूल प्रबंध कार्मिक, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी प्रतिभूति के बारे में कोई विनिधान सलाह सार्वजनिक रूप से पहुंचयोग्य मीडिया, चाहे वास्तविक समय या अवास्तविक समय आधार पर, में तब तक नहीं देंगे, जब तक कि इसके हित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसमें उक्त प्रतिभूति में बिक्री से अधिक खरीद (लांग पोजिशन) या खरीद से अधिक बिक्री (शॉर्ट पोजिशन) सम्मिलित है का प्रकटीकरण न कर दिया गया हो, ऐसी सलाह देते समय।

(2) यदि मध्यवर्ती के निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी या मूल प्रबंध कार्मिक ऐसी सलाह दे रहे हैं, तो मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सलाह देते समय वह अपने हित, अपने आश्रित परिवार के सदस्यों और नियोक्ता के हित, जिसमें नियोक्ता की उक्त प्रतिभूति में बिक्री से अधिक खरीद या खरीद से अधिक बिक्री सम्मिलित है, को भी प्रकट करता है।

(3) मध्यवर्ती किसी ग्राहक या विनिधानकर्ता (निवेशक) को सिफारिश नहीं करेगा, जिससे ऐसे प्रत्याशा हो कि वह किहीं प्रतिभूतियों को अर्जित करने, इनका निपटान करने या इन्हें रखे रहने के लिए उस पर निर्भर हो सकेगा, जब तक कि उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार न हों कि सिफारिश उपयुक्त है।

16. आचार संहिता.—मध्यवर्ती और इसके निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी और मूल प्रबंध कार्मिक अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का सतत रूप से पालन करेंगे।

अध्याय IV

निरीक्षण और अनुशासनिक कार्यवाहियाँ

17. बोर्ड द्वारा निरीक्षण का अधिकार .-(1) अधिनियम की धारा 11 और धारा 11ग के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड किसी प्रयोजन के लिए, जिसमें उप-विनियम (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन सम्मिलित हैं, मध्यवर्ती की बहियाँ, लेखों, अभिलेखों, जिनमें टेलीफोन अभिलेख और इलेक्ट्रोनिक अभिलेख और दस्तावेज सम्मिलित हैं, का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे :-

- (क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियाँ, अभिलेख जिनमें टेलीफोन अभिलेख और इलेक्ट्रोनिक अभिलेख और दस्तावेज सम्मिलित हैं, सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में रखे जा रहे हैं;
- (ख) यह अभिनिश्चित करना कि क्या पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों को स्थापित कर लिया गया है और मध्यवर्ती द्वारा इसकी बाध्यताओं की पूर्ति करने के लिए इनका अनुसरण किया जा रहा है, सुसंगत विनियमों के अधीन;
- (ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो मध्यवर्ती को अयोग्य या अपात्र बना दें;
- (घ) यह अभिनिश्चित करना कि क्या प्रतिभूति विधियों के उपबंधों और तदधीन जारी निरेशों या परिपत्रों का अनुपालन किया जा रहा है;
- (ङ) मध्यवर्ती के क्रियाकलापों से सम्बन्धित किसी मामले पर विनिधानकर्ताओं (निवेशकों), ग्राहकों, अन्य बाजार सहभागियों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करना;
- (च) स्वप्रेरणा से ऐसे मामलों की जांच करना जैसा विनिधानकर्ताओं या प्रतिभूति बाजार के हित में ठीक समझा जाए।

18. निरीक्षण के पूर्व सूचना (नोटिस) .-(1) विनियम 17 के अधीन निरीक्षण करने से पूर्व, निरीक्षण प्राधिकारी सम्बद्ध मध्यवर्ती को सूचना (नोटिस) देगा :

परंतु यह कि जहाँ निरीक्षण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में कोई ऐसी सूचना नहीं दी जानी चाहिए, तो यह, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसी सूचना से अभिमुक्त दे सकेगा।

(2) निरीक्षण के दौरान, मध्यवर्ती विनियम 19 के अधीन उपबंधित अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आबद्ध होगा।

19. निरीक्षण के सम्बंध में मध्यवर्ती की बाध्यताएँ .-(1) मध्यवर्ती के प्रत्येक निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, न्यासी, अधिकारी, कर्मचारी और किसी एजेंट जिसका निरीक्षण किया जा रहा है, का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखी ऐसी बहियाँ, लेखे, अभिलेख जिनमें टेलीफोन अभिलेख और इलेक्ट्रोनिक अभिलेख और दस्तावेज सम्मिलित हैं, निरीक्षण प्राधिकारी को पेश करे और इसके क्रियाकलापों से सम्बन्धित ऐसे विवरण और जानकारी ऐसे समय के भीतर निरीक्षण प्राधिकारी को दे जैसी निरीक्षण प्राधिकारी अपेक्षा करे।

(2) मध्यवर्ती निरीक्षण प्राधिकारी को उस परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच रखने के लिए अनुमति करेगा, जिसका अधिभोगी ऐसा मध्यवर्ती या इसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति है, और किन्हीं बहियाँ, अभिलेखों, जिनमें टेलीफोन अभिलेख और इलेक्ट्रोनिक अभिलेख और दस्तावेज सम्मिलित हैं, जो मध्यवर्ती या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के कब्जे में हों, की परीक्षा करने के लिए उचित सुविधा भी देगा और दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियाँ भी उपलब्ध करायेंगा जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हैं।

(3) अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरीक्षण प्राधिकारी, निरीक्षण के दौरान, ऐसे मध्यवर्ती के किसी प्रधान अधिकारी, निदेशक, न्यासी, भागीदार, स्वत्वधारी या कर्मचारी के कथनों की परीक्षा करने या को अभिलिखित करने का हकदार होगा।

(4) ऐसे मध्यवर्ती के प्रत्येक निदेशक, स्वत्वधारी, न्यासी, भागीदार अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को समस्त सहायता दे जैसी निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के सम्बंध में युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे।

20. लेखापरीक्षक या मूल्यांकक की नियुक्ति .-(1) बोर्ड मध्यवर्ती की लेखा बहियों या कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए अहित लेखापरीक्षक को नियुक्त कर सकेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक के यास निरीक्षण प्राधिकारी की वही शक्तियाँ होंगी, विनियम 17 में उल्लिखित, और मध्यवर्ती तथा इसके कर्मचारियों की बाध्यता, विनियम 19 में उल्लिखित, इस विनियम के अधीन निरीक्षण के प्रति लागू होंगी।

स्पष्टीकरण : इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, पद “अहित लेखापरीक्षक (संपरीक्षक)” का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 से प्राप्त है।

(2) बोर्ड अहित मूल्यांकक को नियुक्त कर सकेगा या मध्यवर्ती द्वारा अहित मूल्यांकक को नियुक्त किये जाने का निदेश दे सकेगा, यदि ऐसा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(3) उप-नियम (1) के अधीन ऐसी लेखापरीक्षा या उप-विनियम (2) के अधीन मूल्यांकन के व्यय मध्यवर्ती द्वारा उठाये जायेंगे।

21. बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.—(1) निरीक्षण प्राधिकारी बोर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें अंतरिम रिपोर्ट भी सम्मिलित हैं प्रस्तुत करेगा।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर, बोर्ड उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जैसी यह ठीक तथा समुचित समझे।

अध्याय V

चूक की दशा में कार्रवाई और प्रमाणपत्र के निलम्बन या रद्दकरण की नीति

22. परिभाषाएँ.—इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “उत्तर की प्राप्ति की तारीख” में वह तारीख सम्मिलित है जिस तारीख को नोटिसी मौखिक निवेदन, यदि कोई हों, करता है;
- (ख) “पदाभिहित प्राधिकारी” से बोर्ड का अधिकारी अभिप्रेत है और जिसमें ऐसे अधिकारियों का बैच सम्मिलित है, विनियम 24 के अधीन नियुक्त;
- (ग) “पदाभिहित सदस्य” से इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित बोर्ड का अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है;
- (घ) “नोटिसी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इस अध्याय के अधीन सूचना (नोटिस) जारी की गयी हो।

23. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलम्बन और अन्य कार्रवाइयाँ.—जहाँ कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो—

- (क) किन्हीं शर्तों जिनके अध्यधीन उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है का अनुपालन करने में असफल रहता है;
- (ख) प्रतिभूति विधियों के उपबंधों अथवा तद्धीन जारी निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों में से किसी का उल्लंघन करता है;

तो वहाँ बोर्ड, प्रतिभूति विधियों अथवा तद्धीन जारी निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा ऐसी कार्रवाई इन विनियमों के अधीन उपबंधित रीति में कर सकेगा।

24. पदाभिहित पदाधिकारी की नियुक्ति.—(1) जहाँ पदाभिहित सदस्य को यह प्रतीत होता है, कि किसी व्यक्ति, जिसे अधिनियम, तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण

प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, ने विनियम 23 में विनिर्दिष्ट स्वरूप की कोई चूक की है, तो वह ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जो प्रभाग मुख्य की पंक्ति से नीचे का न हो, पदाभिहित प्राधिकारी के रूप में :

परंतु यह कि पदाभिहित सदस्य, स्वविवेकानुसार, तीन अधिकारियों का बैच नियुक्त कर सकेगा, जिनमें से प्रत्येक प्रभाग मुख्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसे बैच की अध्यक्षता उसके द्वारा की जाएगी जो उनमें से ज्येष्ठतम् हो और ऐसे बैच के सभी विनिश्चय या सिफारिशें बहुमत के रूप में होंगी।

(2) किसी भी अधिकारी, जिसने अधिकथित अतिक्रमण की बाबत अन्वेषण या निरीक्षण किया हो, को पदाभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

25. सूचना जारी करना.—(1) पदाभिहित प्राधिकारी, यदि यह ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त आधार पाता है, सम्बद्ध व्यक्ति को सूचना उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए जारी करेगा कि इसको प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलम्बित या रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए या इसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना उस उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करेगी जिसके सम्बंध में यह अभिकथन है कि वह नोटिसी द्वारा किया गया है, अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धांतों को उपर्युक्त करते हुए जिनकी बाबत उल्लंघन होने का अभिकथन है।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन जारी सूचना से, दस्तावेजों जिन पर अभ्यारोपण करने में निर्भर रहा गया हो की प्रतियाँ और किए गए अन्वेषण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में निकाले गये निष्कर्षों से युक्त दस्तावेजों, रिपोर्टों के सुसंगत भागों के उद्धरण उपाबद्ध किये जायेंगे।

(4) नोटिसी से यह अपेक्षित होगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के भीतर, उसकी तारीख की तारीख से इककीस दिनों से अनधिक, लिखित अभ्यावेदन पदाभिहित प्राधिकारी को अभ्यावेदन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करे।

26. नोटिसी द्वारा उत्तर.—(1) नोटिसी पदाभिहित प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि पदाभिहित प्राधिकारी पर्याप्त आधारों से, जो नोटिसी द्वारा दर्शाये गए हों, और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा।

(2) यदि नोटिसी कारण बताओ सूचना का उत्तर नहीं देता है, तो पदाधिकारी मामले में एकपक्षीय रूप से कार्यवाही कर सकेगा, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए और, यथास्थिति, इसके समक्ष उपलब्ध तात्त्विक तथ्यों के आधार पर सिफारिश कर सकेगा।

27. घूँक की दशा में कार्रवाई।—नोटिसी के अध्यावेदनों, यदि कोई हों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और विधि के लागू उपबंधों या बोर्ड द्वारा प्रशासित निदेशों, अनुदेशों या परिपत्रों पर विचार करने के पश्चात्, पदाधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जहाँ तथ्यों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो, निम्नलिखित की सिफारिश करते हुए—

- (i) विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलम्बन;
- (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण;
- (iii) नोटिसी को आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई नया कर्तव्यभार या संविदा लेने या नई स्कीम चालू करने से प्रतिषिद्ध करना;
- (iv) नोटिसी के प्रधान अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती या अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के साथ नियोजित या सहयुक्त होने से विवर्जित करना;
- (v) नोटिसी की शाखा या कार्यालय को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए क्रियाकलाप करने से विवर्जित करना;
- (vi) नोटिसी को चेतावनी देना।

28. सिफारिश की प्राप्ति पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया।

(1) पदाधिकारी से रिपोर्ट, जिसमें उपायों की सिफारिश की गयी हो, की प्राप्ति पर, पदाधिकारित सदस्य उस पर विचार करेगा और नोटिसी को कारण बताओ सूचना, पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए, नोटिसी से यह अपेक्षा करते हुए जारी करेगा कि वह अपना लिखित अध्यावेदन प्रस्तुत करे कि कार्रवाई, जिसमें समुचित निदेश पारित करना सम्मिलित है, जो पदाधिकारित सदस्य समुचित समझता है, क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) नोटिसी, सूचना की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर पदाधिकारित सदस्य को उत्तर भेज सकेगा जो उत्तर, यदि कोई नोटिसी से प्राप्त हो, पर विचार करने और व्यक्ति को सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात् समुचित आदेश पारित कर सकेगा, यथासम्भव शीघ्रता के साथ, और सूचना के उत्तर की प्राप्ति या सुनवाई की तारीख से एक सौ इक्कीस दिनों के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास किया जाएगा।

29. एक ही आदेश।—पदाधिकारित सदस्य कई नोटिसियों की बावत एक ही आदेश पारित कर सकेगा जहाँ प्रश्नगत विषय वस्तु सारभूत रूप से उसी या वैसे ही स्वरूप की है।

30. आदेश की सूचना।—(1) इस अध्याय के अधीन पदाधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट और पदाधिकारित सदस्य द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) इस अध्याय के अधीन पारित आदेश की प्रति नोटिसी को भेजी जाएगी और बोर्ड के वेबसाइट पर भी डाली जाएगी।

(3) यदि नोटिसी स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम, निक्षेपागार या स्व-विनियामक संगठन का सदस्य है, तो आदेश की प्रति सम्बद्ध स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम, निक्षेपागार या स्व-विनियामक संगठन को भी भेजी जाएगी।

31. किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अध्यर्पण।

(1) कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, जो अपना क्रियाकलाप छोड़ना और प्रमाणपत्र अध्यर्पित करना चाहता है, बोर्ड को ऐसे अध्यर्पण के लिए निवेदन कर सकेगा और ऐसे निवेदन का निपटारा करते समय, बोर्ड इस अध्याय के पूर्वामी उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होगा।

(2) इस विनियम के अधीन निवेदन का निपटारा करते समय, बोर्ड सम्बद्ध व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उन कारकों के सम्बन्ध में बोर्ड का समाधान करे जो यह ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं किन्तु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं—

- (क) सुसंगत विनियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को रखने और इनके परिरक्षण के लिए व्यक्ति द्वारा किए गए इंतजाम;
- (ख) विनिधानकर्ता (निवेशक) शिक्यतों को दूर करना;
- (ग) अपने ग्राहकों के अभिलेखों, निधियों या प्रतिभूतियों का अंतरण;
- (घ) ग्राहकों के लिए सेवा जारी रहना सुनिश्चित करने के लिए इसके द्वारा किए गए इंतजाम;
- (ङ) चूंके और लम्बित कार्रवाई, यदि कोई हो।

(3) अध्यर्पण को स्वीकार करते समय, बोर्ड व्यक्ति पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो यह विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) या इसके ग्राहकों के संरक्षण या प्रतिभूति बाजार के लिए ठीक समझे और ऐसा व्यक्ति ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा।

32. विवर्जन, निलम्बन, रद्दकरण या अध्यर्पण का प्रभाव।

(1) विवर्जन या प्रमाणपत्र के निलम्बन की तारीख से ही, सम्बद्ध व्यक्ति—

- (क) किसी नये कर्तव्यभार या संविदा का जिम्मा नहीं लेगा या कोई नई स्कीम चालू नहीं करेगा और ऐसे विवर्जन

या निलम्बन की कालावधि के दौरान यह कोई वह क्रियाकलाप करना छोड़ देगा जिसकी बाबत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था;

(ख) अपने ग्राहकों या विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को अपनी अभिरक्षा में धारित उनकी प्रतिभूतियों या निधियों को वापस लेने या अंतरित करने या इसको दिए गए किसी कर्तव्यभार को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा, ऐसे ग्राहक या विनिधानकर्ता के प्रति किसी अतिरिक्त लागत के बिना;

(ग) इसके द्वारा उपगत या ग्रहण किए गए दायित्व के विषय में व्यवस्थाएँ करेगा;

(घ) ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा, जिसमें विनिधानकर्ताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों और प्रतिभूतियों या धन, जो ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में हों, से संबंधित कार्रवाई सम्मिलित है, ऐसी समय कालावधि के भीतर और रीति में, जैसा सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित किया जाए या जैसा बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए, इस अध्याय के अधीन आदेश पारित करते समय या अन्यथा।

(2) अध्यर्पण या प्रमाण-पत्र के रद्दकरण की तारीख से ही, संबद्ध व्यक्ति—

(क) इस प्रकार रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड को लौटायेगा और स्वयं को वह क्रियाकलाप करने के प्रमाणपत्र के धारक के रूप में नहीं जतायेगा जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था;

(ख) कोई वह क्रियाकलाप करना छोड़ देगा जिसकी बाबत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था;

(ग) अपने क्रियाकलाप ऐसे दूसरे मध्यवर्ती को अंतरित करेगा जो ऐसा क्रियाकलाप करने के लिए विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक करता हो और अपने ग्राहकों या विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को अपनी अभिरक्षा में धारित उनकी प्रतिभूतियों या निधियों को वापस लेने या अंतरित करने या इसको दिए गए किसी कर्तव्यभार को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा, ऐसे ग्राहक या विनिधानकर्ता के प्रति किसी अतिरिक्त लागत के बिना;

(घ) इसके द्वारा उपगत या ग्रहण किये गये दायित्व के विषय में व्यवस्थाएँ करेगा;

(ङ) ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा, जिसमें विनिधानकर्ताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों और प्रतिभूतियों या धन, जो ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में हों, से संबंधित कार्रवाई सम्मिलित है, ऐसी समय कालावधि

के भीतर और रीति में, जैसा सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित किया जाए या जैसा बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए, इस अध्याय के अधीन आदेश पारित करते समय या अन्यथा।

33. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (अपील अधिकरण)— इन विनियमों के अधीन आदेश से व्यक्ति व्यक्ति अधिनियम की धारा 15 और इस संबंध में विहित नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसे आदेश के विरुद्ध प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (अपील अधिकरण) को अपील कर सकेगा।

अध्याय VI

विविध

34. सूचना और आदेश की तामील की रीति और आदेश का प्रकाशन।—(1) इन विनियमों के अधीन जारी कोई सूचना या पारित आदेश की तामील—

(क) संबद्ध व्यक्ति या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट (अधिकर्ता) को हस्त परिदान (हैंड डिलीवरी) द्वारा की जा सकेगी; या

(ख) परिदान (डिलीवरी) द्वारा बोर्ड के रिकार्ड में उपलब्ध पते पर और उस व्यक्ति या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट को संबोधित, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा या इलेक्ट्रोनिक मेल सेवा द्वारा या पारेशन के किन्हीं अन्य साधनों द्वारा जो परिदान का रिकार्ड प्रदान करते हों कि जा सकेगी; या

(ग) स्टॉक दलाल या उप-दलाल या निक्षेपागार सहभागी के मामले में क्रमशः संबद्ध स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से की जा सकेगी; और

(घ) यदि इसकी तामील खण्ड (क) या (ख) या (ग) के अनुसार नहीं की जा सकती है, तो उस परिसर के दरवाजे या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर उसे लगाते हुए की जा सकेगी जिसमें ऐसा व्यक्ति निवास करता है या जो उसका अंतिम ज्ञात निवास-स्थान है या जिसमें कारबार चलाता है या जो उसका अंतिम ज्ञात कारबार-स्थान है या जिसमें स्वयं अभिलाभ के लिए काम करता है या जो उसका स्वयं अभिलाभ के लिए काम करने का अंतिम ज्ञात स्थान है।

(2) इन विनियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश बोर्ड के वेबसाइट पर डाला जाएगा।

35. निदेश।— प्रतिभूति विधियों के अधीन किसी आदेश और निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों जो तद्धीन जारी किये जायें, जिसमें इन विनियमों के अध्याय V के अधीन आदेश सम्मिलित है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड प्रतिभूति बाजार के हित में,

विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में या किसी मध्यवर्ती के उचित प्रबंध को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, आवश्यक निदेश, जिसमें निमलिखित में से कोई या सभी सम्मिलित हैं किन्तु जो इन तक ही सीमित नहीं है, जारी कर सकेगा—

(क) मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार से सहयुक्त अन्य व्यक्तियों को किसी स्कीम के अधीन या अन्यथा विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) से एकत्रित कोई धन या प्रतिभूतियाँ लौटाने का निदेश देना, व्याज सहित या रहित;

(ख) मध्यवर्ती या प्रतिभूति बाजार से सहयुक्त अन्य व्यक्तियों को विनिष्ट कालावधि के लिए पूँजी बाजार में पहुंच न रखने या प्रतिभूतियों में व्यौहार न करने या किसी मध्यवर्ती से अथवा किसी पूँजी बाजार संबंधित क्रियाकलाप से सहयुक्त न होने का निदेश देना;

(ग) संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को पारस्परिक निधि या सामूहिक विनिधान (निवेश) स्कीम द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों या यूनिटों में व्यापार की अनुशा न देने का निदेश देना;

(घ) संबद्ध मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को पारस्परिक निधिया सामूहिक विनिधान (निवेश) स्कीम द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों या यूनिटों में व्यापार को निर्लिपित करने का निदेश देना;

(ङ) कोई अन्य निदेश जो बोर्ड मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त तथा उचित समझे:

परन्तु यह कि किन्हीं निदेशों को जारी करने से पूर्व बोर्ड संबद्ध व्यक्तियों को सुने जाने का उचित अवसर देगा:

परंतु यह और कि यदि परिस्थितियों के अनुसार कोई अंतरिम निदेश तुरंत पारित किया जाना अपेक्षित है, तो बोर्ड निदेश पारित करने के पश्चात् संबद्ध व्यक्तियों को सुने जाने का उचित अवसर देगा, बिना किसी अनुचित विलंब के।

36. स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति—इन विनियमों के लागू होने या निर्वचन में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड परिषदों के रूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा।

37. अन्य विनियमों में संशोधन—अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट विनियम, उसमें कथित रीति में और विस्तार तक, संशोधित हो जाएंगे।

38. निरसन और व्यावृत्तियाँ—(1) राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन से—

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002; और

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उन विनियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अधीन प्रारंभ की गई जांच या जारी की गई सूचना सम्मिलित है, राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन से पूर्व, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या प्रारंभ की गई समझी जाएगी।

(3) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विनियमों के निरसन के पश्चात्, किसी विनियम, मार्गदर्शक सिद्धांतों, परिषदों में उसके प्रति कोई निर्देश क्रमशः अध्याय V और अनुसूची II के प्रति निर्देश समझा जाएगा।

अनुसूची I

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती विनियम, 2008

[विनियम 3]

प्ररूप क

प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

इसमें अंतर्विष्ट जानकारी तारीख/मास/वर्ष को अद्यतन की गई है:

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश—

- आवेदकों को संपूर्ण आवेदन प्ररूप, बोर्ड को अनिवार्यतः समुचित समर्थक दस्तावेजों और लागू आवेदन फीस के साथ, प्रस्तुत करना होगा। समर्थक दस्तावेज नोटरी पत्रिक द्वारा सत्य रूप में अनुप्राप्तित किये जाने चाहिए।
- यह आवेदन प्ररूप विनियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए।
- रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा, केवल यदि यह सभी प्रकार से पूर्ण है।
- सभी उत्तर अनिवार्यतः टाइप किये हुए होने चाहिए।
- जानकारी जिसे अधिक विस्तारपूर्वक देने की आवश्यकता है अलग पन्नों पर दी जा सकेगी जो आवेदन प्ररूप से संलग्न होने चाहिए।
- आवेदन पर सभी हस्ताक्षर अनिवार्यतः मूल होने चाहिए।
- प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ और प्रत्येक अतिरिक्त पन्ने पर आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के आदाक्षर अनिवार्यतः होने चाहिए।

भाग-I

1. आवेदक और इसके सहबद्धों के साधारण व्यौरे: प्रबंध अनुपालन मैट्रिक्स/संरचना

1.1. आवेदक का नाम:

1.2. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, पत्राचार के लिए पता, टेलिफोन संख्याएँ, फैक्स संख्याएँ, ई-मेल, वेबसाइट, संपर्क व्यक्ति का नाम और टेलिफोन संख्या, शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो:

1.3. निगमन/स्थापना की तारीख और स्थान और कंपनी रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दी गयी रजिस्ट्रीकरण संख्या:

1.4. आवेदक की विधिक हैसियत और विधि जिसके अधीन यह निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत है, यदि कोई हो, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि जहाँ आवेदक सूचीबद्ध सत्ता है, उन एक्सचेंजों (चाहे भारत में या विदेश में) के ब्यौरे जहाँ आवेदक सूचीबद्ध है:

1.5. आवेदक के मुख्य क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण: (आवेदक के गठन संबंधी दस्तावेजों की प्रतियों के साथ)

1.6. ऐसे क्रियाकलाप के प्रारंभ का वर्ष (यदि लागू हो):

1.7. आवेदक का शेयरधारिता पैटर्न (कृपया सभी ऐसे व्यक्तियों के नाम दें जो चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कंपनी में शेयरधारिता या मताधिकारों के 5% से अधिक धारण करते हैं):

शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	(शेयरधारिता का%)/ (मताधिकारों का %)
-----------------	------------------	--

जहाँ आवेदक पर नियंत्रण का प्रयोग व्यक्ति द्वारा करार या इंतजाम के रूप में किया जाता है, तो यथास्थिति ऐसे करार या इंतजाम के संबंध में ब्यौरे और दस्तावेजीकरण।

1.8. भारत या विदेश में क्रियाशील आवेदक के महत्वपूर्ण सहबद्धों और उनके द्वारा किये गये क्रियाकलापों के ब्यौरे, प्रत्येक ऐसे सहबद्ध की विधिक हैसियत और विधि, जिसके अधीन यह निगमित, स्थापित या रजिस्ट्रीकृत है, यदि कोई हो, के ब्यौरों सहित

विधिक हैसियत और रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे :

नाम

पता

टेलीफोन सं.

फैक्स सं.

ई-मेल

सहबद्ध में आवेदक के हित का स्वरूप, यदि कोई हो

आवेदक में ऐसे सहबद्ध के हित का स्वरूप, यदि कोई हो

1.9. बोर्ड के पास और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के पास या स्टॉक एक्सचेंजों अथवा स्व-विनियामक संगठन (चाहे भारत में या विदेश में) के पास आवेदक के रजिस्ट्रीकरण/उसकी मान्यता के ब्यौरे:

विनियामक /स्व विनि-	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे	रजिस्ट्रीकरण संगठन	विधिमान्यता की कालावधि
---------------------	------------------------	--------------------	------------------------

1.10. बोर्ड के पास या अन्य विनियामक प्राधिकरण के पास या स्टॉक एक्सचेंजों अथवा स्व-विनियामक संगठनों (चाहे भारत में या विदेश में) के पास आवेदक के प्रत्येक सहबद्ध के रजिस्ट्रीकरण/उनकी मान्यता के ब्यौरे:

विनियामक /स्व विनि-	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे	रजिस्ट्रीकरण संगठन	विधिमान्यता की कालावधि
---------------------	------------------------	--------------------	------------------------

1.11 अनुपालन अधिकारी के ब्यौरे:

नाम	कार्य-पदनाम	कारबार का पता	टेलिफोन सं.	फैक्स सं.	ई-मेल
-----	-------------	---------------	-------------	-----------	-------

1.12 प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे:

व्यक्ति का नाम	जिम्मेदारी	अर्हता/अनुभव
----------------	------------	--------------

1.13 मूल प्रबंध कार्मिक के ब्यौरे:

व्यक्ति का नाम	जिम्मेदारी	अर्हता/अनुभव
----------------	------------	--------------

1.14 आवेदक की किसी दोषसिद्धि या उसके दिवालियेपन/परिसमापन की किसी घोषणा के ब्यौरे।

1.15 किसी विनियामक प्राधिकरणों द्वारा आवेदक या इसके सहबद्धों के विरुद्ध की गयी कार्रवाईयों के ब्यौरे।

क्र.सं.	प्राधिकरण	अभिकथित चूक का विवरण	की गई कार्रवाई	वर्तमान स्थिति
---------	-----------	----------------------	----------------	----------------

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए “सहबद्ध” से जहाँ आवेदक कंपनी है, इसकी धारिता (होलिडंग) कंपनी और इसके समनुवंगी और जहाँ आवेदक व्यक्ति है इसके आश्रित नातेदार अभिप्रेत होंगे।

2. माध्यस्थम्/मुकदमों के ब्यौरे जिसका मध्यवर्ती की कार्यप्रणाली और विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों पर तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

2.1 तीन मास से अधिक के लिए लंबित शिकायतें:

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्ति का संक्षिप्त विवरण	शिकायत वर्तमान स्थिति

2.2 माध्यस्थप/मुकदमेबाजी के मामले:

मंच (फोरम)	अर्जीदार का नाम	मामले का	कार्यवाहियों की वर्तमान अवस्था	परित अंतिम पंचाट	(अवार्ड/व्यौरे)

3. समूह का संक्षिप्त विवरण

3.1 समूह, यदि कोई हो, का संक्षिप्त विवरण, जिससे आवेदक संबंधित है। कृपया कपनी और समूह के ब्यौरों की पुष्टि करें, उन अलग-अलग व्यक्तियों का पता लगाते हुए जो नियंत्रण कर रहे हैं।

4. प्रबंधतत्र के ब्यौरे:

4.1 यथास्थिति आवेदक के निदेशकों/भागीदारों/न्यासियों के निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करायें:

नाम
आवेदक में हित के ब्यौरे
अन्य सत्ताओं में निदेशक पद
अन्य संस्थाओं में नियंत्रक हित

4.2 आवेदक के संप्रवर्तकों के नाम उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

भाग-II

5. वित्तीय रिपोर्ट देना और प्रकट करना (जहाँ मध्यवर्ती सक्रिय है) :

5.1 पिछले तीन वर्षों के लिए, लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि लेखा विवरण (लेखों की टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए):

5.2 पिछले तीन वर्षों के लिए, आवेदक की शुद्ध मालियत, आवेदक का खंड के अनुसार व्यापारावर्त (टर्नओवर) (जहाँ आवश्यक हो) [उदाहरण के लिए जहाँ आवेदक स्टॉक दलाल है, वहाँ खंड के अनुसार व्यापारावर्त अर्थात् नकदी खंड, व्युत्पन्नी खंड, वस्तु (कमेडीटी) खंड इत्यादि के अधीन व्यापारावर्त उपलब्ध कराया जा सकेगा]।

6. कराधान प्राधिकरण के ब्यौरे:

6.1 कृपया उस प्राधिकरण के ब्यौरे उपलब्ध करायें जहाँ आवेदक कराधान के अधीन है।

6.2 आवेदक और इसके निदेशकों की स्थायी खाता संख्या/रजिस्ट्रीकरण संख्या/कोड, कर प्राधिकरण द्वारा दिया गया (यदि कोई हो), जो लागू हो:

7. संप्रवर्तकों और प्रबंध कार्मिक के ब्यौरे:

7.1 आवेदक के संप्रवर्तकों का पता और संपर्क संबंधी ब्यौरे (जिसमें टेलिफोन संख्याएँ, ई-मेल, फैक्स इत्यादि सम्मिलित हैं) उपलब्ध करायें जैसा प्रारूप के भाग-1 के खंड 4.2 में विवरित है।

7.2 आवेदक के प्रबंध कार्मिक का पता और संपर्क संबंधी ब्यौरे (जिसमें टेलिफोन संख्याएँ, ई-मेल, फैक्स इत्यादि सम्मिलित हैं) उपलब्ध करायें जैसा प्रारूप के भाग-1 के खंड 4.1 में विवरित है।

7.3 आवेदक के निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या उपलब्ध करायें।

8. आवेदक द्वारा किसी विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त किन्हीं कारण बताओ सूचनाओं के ब्यौरे :

क्र.सं.	सूचना की तारीख	अभिकथित अतिक्रमण के ब्यौरे	वर्तमान स्थिति

9. वचन और घोषणा:

हम एतद्वारा व्यपदेशन करते हैं, वारंटी देते हैं और घोषणा करते हैं कि:

1. आवेदन, जिसमें उससे संलग्नक पन्ने भी सम्मिलित हैं, में दी गयी जानकारी सभी प्रकार से पूर्ण, सत्य और सही है;

2. हम प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए लागू सभी मानदंड और शर्तों का अनुपालन करते हैं, और हमने इनका अनुसरण किया है तथा इन्हें पूरा किया है;

3. हम यह भी वचन देते हैं कि हम आवेदन में उपलब्ध करायी गयी जानकारी में किसी परिवर्तन की सूचना तुरंत, विनियमों के अधीन यथा रीती में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को देंगे;

4. हम यह भी वचन देते हैं कि हम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और नियमों, विनियमों के उपबंधों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और किन्हीं अन्य निदेशों, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर पारित किये जाएँ, तद्धीन जारी और हम पर लागू, और सभी अन्य सुसंगत विधियों जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित हैं का अनुपालन करेंगे।

5. हम यह भी वचन देते हैं कि प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शर्त के रूप में, हम कार्यचालन संबंधी ऐसे अनुदेशों/निदेशों का पालन करेंगे जो अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए जाएँ।

(आवेदक का नाम) के लिए और की ओर से
आवेदक का नाम

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

ओहदा

तारीख तारीख/मास/वर्ष

टिप्पणियाँ:

अनुसूची II

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008

[विनियम 7 देखें]

‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ का अवधारणा करने के
लिए मानदंड

यह अवधारणा करने के प्रयोजन लिए कि क्या आवेदक या
मध्यवर्ती “उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति” है बोर्ड कोई ऐसा विचार
कर सकेगा जैसा यह ठीक समझे, जिसमें आवेदक या मध्यवर्ती,
प्रधान अधिकारी और मूल प्रबंध व्यक्तियाँ, चाहे किसी भी नाम से
पुकारे जाएँ के संबंध में निम्नलिखित मानदंड सम्मिलित हैं किन्तु
निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं—

- (क) सत्यनिष्ठा, ख्याति और चरित्र;
- (ख) दोषसिद्धियों और अवरोध आदेशों का अभाव;
- (ग) क्षमता जिसमें वित्तीय शोधन क्षमता और शुद्ध
मालियत सम्मिलित है।

अनुसूची III

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008

[विनियम 16 देखें]

आचार संहिता

1. विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण

1.1 विनिधानकर्ता/ग्रहक

प्रत्येक मध्यवर्ती विनिधानकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए
समस्त प्रयास करेगा और ग्रहकों की आवश्यकताओं और वातावरण
और अपने वृत्तिकौशल को ध्यान में रखकर सर्वोत्तम संभव सलाह
देगा।

1.2 सेवाओं के उच्च स्तर

मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि यह और इसके मूल प्रबंध
कार्मिक, कर्मचारी, संविदाकार और अभिकर्ता (एजेंट), अपने कारबार
के संचालन में सत्यनिष्ठा, गरिमा, औचित्य, सदाचार और वृत्तिकरण

का पालन करेंगे तथा समस्त वृत्तिकौशल तुरंत, प्रभावी और दक्ष
रीति में किये जाएँगे।

मध्यवर्ती इसके कारबार के संचालन की बाबत अपने कर्मचारियों
और अभिकर्ताओं के कार्यों या लोपों के लिए उत्तरदायी होगा।

1.3 सम्यक् तत्परता बरतना और कोई दुरभिसंधि न करना

मध्यवर्ती सभी समयों पर उच्च स्तरों की सेवा देगा, इसके द्वारा
नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों पर सम्यक् कौशल और तत्परता
बरतेगा, समुचित सतर्कता सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णय
करेगा और किसी भी समय अन्य मध्यवर्तियों के साथ दुरभिसंधि में
ऐसी रीति में कार्य नहीं करेगा जो विनिधानकर्ता(ओं) के लिए
अहितकर है।

1.4 फीस

मध्यवर्ती अपने ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं को समुचित अग्रिम
सूचना के बिना दी गयी सेवाओं के लिए प्रभार/फीस नहीं बढ़ायेगा।

II. रकमों का संवितरण

2.1 रकमों का संवितरण

मध्यवर्ती लाभांशों, व्याजों या अपने ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं
की ओर से इसके द्वारा प्राप्त या एकत्र की गयी कोई ऐसी प्रोद्भवन
आय के संवितरण में तत्पर रहेगा।

III. जानकारी का संवितरण

3.1 मध्यवर्ती सुनिश्चित करेगा कि ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं
को ग्राह्य और सामयिक रिति में पर्याप्त प्रकटीकरण किए जाते हैं
ताकि वे संतुलित और सोच-समझकर विनिश्चय करने में समर्थ हो
सकें।

3.2 मध्यवर्ती कोई दुर्घटपदेशन नहीं करेगा और यह सुनिश्चित
करेगा कि ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं को उपलब्ध करायी गयी जानकारी
भ्रामक नहीं है।

3.3 मध्यवर्ती ग्रहक/विनिधानकर्ता को बढ़ा-चढ़ाकर कोई कथन
नहीं करेगा चाहे मौखिक या लिखित, या तो इसकी अर्हता या अमुक
सेवाएँ देने की क्षमता या अन्य ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं के संबंध में
इसकी उपलब्धियों के बारे में।

3.4 मध्यवर्ती किसी को, या तो मौखिक रूप में, या लिखित
रूप में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अपने ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं के
बारे में कोई गोपनीय जानकारी, जो इसकी जानकारी में आयी हो,
अपने ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना प्रकट नहीं
करेगा सिवाय जहाँ ऐसे प्रकटीकरण तत्समय किसी विधि के अनुपालन
में किये जाने अपेक्षित हैं।

IV. हित विरोध

4.1 मध्यवर्ती हित विरोध से बचेगा और अपने हित का पर्याप्त
प्रकटीकरण करेगा और हित विरोध की किसी स्थिति का समाधान

करने के लिए व्यवस्था रखेगा, जो कारबार के संचालन में उद्भूत हो सकती हो या जहाँ कोई हित विरोध उद्भूत होता हो, साम्यपूर्ण रीति में उसका समाधान करने के लिए युक्तियुक्त कदम उठायेगा। मध्यवर्ती, मध्यवर्ती के तौर पर कार्य करते समय कर्तव्य तथा हित विरोध के इसके संभाव्य स्रोत या संभाव्य क्षेत्रों का समुचित प्रकटीकरण ग्रहक/विनिधानकर्ता को करेगा, जो अन्तर्जल, उददेश्यप्रद तथा अपक्षाती सेवाएँ देने में इसकी योग्यता को हासित करे।

4.2 मध्यवर्ती या इसके निदेशकों में से कोई, या कर्मचारी, जिसके पास संपूर्ण कारबार या पर्याप्त रूप से इसके संपूर्ण कार्यकलापों का प्रबंध हो, या मध्यवर्ती का सहयुक्त, या तो इसके खाते या उनके संबंधित खातों के माध्यम से या उसके परिवार के सदस्यों, नातेदारों या मित्रों के माध्यम से किसी अंतरंग व्यापार में लिप्त नहीं होगा।

V. अनुपालन और कंपनी शासन (कार्पोरेट गवर्नेंस)

5.1 मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कंपनी (कार्पोरेट) नीतियाँ और कंपनी शासन उपलब्ध है। यह भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कपटपूर्ण और छलसाधक संव्यवहारों में नहीं लेगा और यह किसी अन्तर्जल प्रतियोगिता (जिसमें दूसरे मध्यवर्तीयों के ग्रहकों को उत्प्रेरित करने के लिए अन्तर्जल साधनों का आश्रय लेना सम्मिलित है) में लिप्त नहीं होगा जिससे अन्य मध्यवर्तीयों या विनिधान कर्ताओं के हितों को हानि पहुँचने की संभावना है या यह संभावना है कि इससे ऐसे अन्य मध्यवर्ती, किसी कर्तव्यभार के लिए प्रतियोगिता करते समय या इसे निष्पादित करते समय अहितकर स्थिति में आ जाएँ।

5.2 मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक कदम उठायेगा कि ऑकड़े और अभिलेख सतत रूप से रखे जाते हैं और यह कि ऑकड़े या अभिलेख खोयें नहीं या नष्ट न हों। इसके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और ऑकड़ों के लिए, अधिकार बैंक-अप इसके पास सदैव उपलब्ध हो।

5.3 मध्यवर्ती

- (क) भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के लिए मिथ्या बाजार के सृजन;
- (ख) भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के कीमत हेरफेर या इनकी कीमतों के छलसाधन; या
- (ग) प्रतिभूतियों, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं, किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती की बाबत अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी पास करने; या
- (घ) बाजार संतुलन को विकृत करने या जो बाजार की निर्विचलित कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता हो या निजी अभिलाल के लिए किसी क्रियाकलाप में पक्षकार या में अधिकरण या में लिप्त नहीं होगा।

5.4 मध्यवर्ती बोर्ड, या बोर्ड द्वारा पदाधिकारी के साथ सहयोग करेगा, जब कभी अपेक्षित हो और कोई असत्य

कथन नहीं करेगा या बोर्ड को प्रस्तुत किए गए किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या जानकारी में किसी तात्त्विक तथ्य को नहीं छिपायेगा या बोर्ड अथवा अन्य अधिकरणों जिसके पास यह रजिस्ट्रीकृत है, को ऐसी बहियों, दस्तावेजों, पत्राचार और कागजपत्रों या उनके किंसी भाग को प्रस्तुत करने में उपेक्षा नहीं करेगा या में असफल नहीं होगा या इंकार नहीं करेगा, जैसी समय-समय पर माँग की जाए/अनुरोध किया जाए।

5.5 मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकृत प्राप्तिथित में किसी परिवर्तन/बोर्ड द्वारा की गयी किसी दांडिक कार्रवाई या वित्त में किसी तात्त्विक परिवर्तन जो ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल सकते हों की सूचना ग्रहकों/विनिधि क्षमकर्ताओं को तत्परता से दी जाती है और शेष बकाया कोई कारबार, प्रभावित ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं के किन्हीं अनुदेशों के अनुसार अथवा बोर्ड के अनुदेशों और सुसंगत विनियमों के उपबंधों के अनुसार दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अंतरित किया जाता है।

5.6 मध्यवर्ती ज्ञान और क्षमता का समुचित स्तर बनाये रखेगा और यथास्थिति केंद्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य लागू कानूनी या स्व विनियामक या अन्य निकाय के किसी अधिनियम, विनियमों के उपबंधों, परिपत्रों और मार्गदर्शक सिद्धांतों, और जो ऐसे मध्यवर्ती द्वारा किये गये कारबार की बाबत मध्यवर्ती के लिए लागू हों का पालन करेगा। मध्यवर्ती भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अधिनिर्णयक) विनियम, 2003 के अधीन पारित अधिनिर्णयकों के पंचाट (अवार्ड) का भी अनुपालन करेगा।

5.7 मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि इसके द्वारा किसी विधिनियमों, विनियमों, और बोर्ड के या किसी अन्य विनियामक निकाय के निदेशों के किसी तात्त्विक भंग या अनुपालन की बाबत इसके खिलाफ शुरू की गयी किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों, इत्यादि के बारे में सूचना बोर्ड को तत्परता से दी जाती है।

VI. मध्यवर्ती अवसंरचना अपेक्षाएँ

6.1 मध्यवर्ती के पास अंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएँ और वित्ति तथा प्रचालन संबंधी क्षमता होगी, जिससे इसके प्रचालनों, इसके ग्रहकों, विनिधानकर्ताओं और अन्य रजिस्ट्रीकृत सत्ताओं को चोरी, कपट, तथा अन्य बेर्झमारी के कार्यों, वित्तीय अवचार या लोपों से उद्भूत वित्तीय हानि से संरक्षण की युक्तियुक्त प्रत्याशा की जा सकती है।

6.2 बोर्ड के पास किसी अन्य हैसियत/प्रवर्ग में भी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि मध्यवर्ती के रूप में किए गये क्रियाकलापों और अन्य अनुज्ञात क्रियाकलापों के बीच जनशक्ति और अवसंरचना दोनों के संबंध में समुचित दूरी का संबंध रखा जाता है।

6.3 मध्यवर्ती, ग्रहकों/विनिधानकर्ताओं के समाधानप्रद रूप में, ऐसे मध्यवर्ती की हैसियत से इसकी सेवाओं में निर्वहन में समर्थ होने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधा स्थापित करेगा और रखेगा, और मध्यवर्तीयों की प्रचालन संबंधी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को बच्चूबी दस्तावेजी रूप दिया जाएगा और जो प्रचालन संबंधी निर्देशिकाओं द्वारा समर्थित होंगी।

6.4 मध्यवर्ती सभी दस्तावेजों और आँकड़ों के अभिलेख अपनी अभिरक्षा में ऐसी रीति में सूचित करेगा और रखेगा कि किसी भी कारण से मूल अभिलेखों या दस्तावेजों के खो जाने की दशा में ऐसे दस्तावेजों या आँकड़ों का पता लगाना सुकर हो सके।

अनुसूची IV

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती विनियम, 2008

[विनियम 37 देखें]

अन्य विनियमों में संशोधन

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 का संशोधन

(i). विनियम 6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

6क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या निर्गमन बैंककार उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।”

(ii). विनियम 22 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii). विनियम 23 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“चूक की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

23. निर्गमन बैंककार जो अधिनियम, तद्धीन विरचित नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है उनमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक कार्रवाईयों के लिए दायी होगा जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V के अधीन कार्रवाई सम्मिलित है।”

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 का संशोधन

(i) विनियम 9क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

9क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या सामूहिक विनिधान प्रबंध कांपनी उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।

(II). विनियम 56 में शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम कोई मध्यवर्ती विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(III). विनियम 59 में, शब्दों भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का संशोधन

(i). विनियम 5क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

5क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या साख निर्धारण एजेंसी उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।”

(ii). विनियम 33 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii). विनियम 34 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“चूक की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

34. साख निर्धारण एजेंसी जो अधिनियम, तद्धीन विरचित नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करती है उनमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक कार्रवाईयों के लिए दायी होगी जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V के अधीन कार्रवाई सम्मिलित है।”

4. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियम, 1996 का संशोधन

(i). विनियम 6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

6क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या प्रतिभूति अभिरक्षक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।”

(ii) विनियम 25 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएं।

(iii) विनियम 26 में शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 का संशोधन

(i) विनियम ६ के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

6क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या डिब्बेंचर न्यासी उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसंधी II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा ।"

(ii) विनियम 23 में शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) विनियम 25 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का संशोधन

(i) विनियम 6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

६क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या निक्षेपागार और सहभागी उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति हैं, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसंधी ॥ में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा ।"

(ii) विनियम 63 में शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी) द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने

के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002'' के लिए शब्द ''भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) विनियम 64 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारीं) द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता) विनियम, 1995 का संशोधन

(i) विनियम 6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

‘उपर्युक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

६क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।"

(ii). विनियम 21 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

‘चूक की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

21. विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता जो अधिनियम, तदधीन विरचित नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है उनमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक कार्रवाईयों के लिए दायी होगा जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V के अधीन कार्रवाई सम्मिलित है ।”

8. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी जोखिम पैंजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 का संशोधन

(i) विनियम 4क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

४क. यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए क्या आवेदक या विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।''

(ii) विनियम 23 में शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेट बैंककार) विनियम, 1992 का संशोधन

(i) विनियम-6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

६क. यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या मर्केट बैंककार उपस्थुति तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा । ”

(ii) विनियम 33 में शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) विनियम 35 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘चूक की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

35 मर्चैट बैंकार जो अधिनियम, तदधीन विरचित नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है उनमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक कार्रवाईयों के लिए दायी होगा जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V के अधीन कार्रवाई सम्मिलित है।"

10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का संशोधन

(i) विनियम 7क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

7क. यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या पारस्परिक निधि उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।”

(ii) विनियम 65 में शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) विनियम 68 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरेपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति

और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संविभाग (पोर्टफोलिया) (प्रबंधक) विनियम, 1993 का संशोधन

(i) विनियम 6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

‘‘उपदेश तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड

६क. यह अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदंड पर विचार कर सकेगा।"

(ii) विनियम 28 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) विनियम 30 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“चूक की दशा में कार्बाई के लिए दायित्व

30. संविभाग (पोर्टफोलियो) प्रबंधक जो अधिनियम, तदधीन विरचित नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है उनमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक कार्रवाईयों के लिए हायी होगा जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V के अधीन कार्रवाई सम्मिलित है।”

12. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अधिकारी) विनियम, 1993 का संशोधन

(i) विनियम 6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदण्ड

6क. यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या निर्गम रजिस्ट्रर और शेयर अंतरण अभिकर्ता उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची ॥ में विनिर्दिष्ट मानदण्ड पर विचार कर सकेगा । ॥

(ii) विनियम 20 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 के

लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (iii) विनियम 22 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का संशोधन

- (i) विनियम 5क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदण्ड

- (i) 5क. यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या स्टॉक दलाल, उप-दलाल, व्यापारिक सदस्य और समाशोधन सदस्य उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदण्ड पर विचार कर सकेगा।”
- (ii) विनियम 23 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (iii) विनियम 25 के उप-विनियम (ii) में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (iv) विनियम 27 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

14. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 का संशोधन

- (i) विनियम 6क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदण्ड

6क. यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या हामीदार उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदण्ड पर विचार कर सकेगा।”

- (ii) विनियम 23 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (iii) विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“चूक की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व

25. हामीदार जो अधिनियम, तदधीन विरचित नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करता है उनमें विनिर्दिष्ट एक या अधिक कार्रवाइयों के लिए दायी होगा जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 के अध्याय V के अधीन कार्रवाई सम्मिलित है।”

15. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियां) विनियम, 1996 का संशोधन

- (i) विनियम 4क के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदण्ड

4क. यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या आवेदक या जोखिम पूँजी निधि उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानदण्ड पर विचार कर सकेगा।”

- (ii) विनियम 30 में, शब्दों “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002” के लिए शब्द “भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती), विनियम, 2008 के अध्याय V” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/69 जैड बी/2008/असाधारण]

**SECURITIES AND EXCHANGE
BOARD OF INDIA**
NOTIFICATION

Mumbai, the 26th May, 2008

**Securities and Exchange Board of India
(Intermediaries) Regulations, 2008**

CAD-NRO/GN/2008/11/126538.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Board hereby makes the following regulations, namely:—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force in relation to different classes of intermediaries on such dates as the Board may by notification in the Official Gazette appoint:

Provided that the provisions of Chapters V and VI of these regulations shall come into force on the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); (b) “associate” means any person controlled, directly or indirectly, by the intermediary, or any person who controls, directly or indirectly, the intermediary, or any entity or person under common control with such intermediary, and where such intermediary is a natural person will include any relative of such intermediary and where such intermediary is a body corporate will include its group companies (as defined in the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (Act No. 54 of 1969) or any re-enactment thereof) or companies under the same management;
- (c) “certificate” means a certificate of registration granted to an intermediary by the Board under the relevant regulations;
- (d) “change of status or constitution”, in relation to an intermediary includes—
 - (i) amalgamation, demerger, consolidation or any other kind of corporate restructuring falling within the Scope of Section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the corresponding provision of any other law for the time being in force or any agreement or arrangement which would have the effect of such corporate restructuring;

- (ii) any change in control of the intermediary;
- (iii) any change in the legal status of the intermediary;
- (e) “control”, in relation to an intermediary shall include the power to, directly or indirectly, control the management or policy decisions of such intermediary by person or persons acting individually or in concert;
- (f) “Form” means a Form in Schedule I;
- (g) “intermediary” means a person mentioned in clauses (b) and (ba) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (IA) of Section 12 of the Act and includes an asset management company in relation to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, a clearing member of a clearing corporation or clearing house and a trading member of a derivative segment of a stock exchange but does not include foreign institutional investor, foreign venture capital investor, mutual fund, collective investment scheme and venture capital fund;
- (h) “inspecting authority” means one or more persons appointed by the Board to undertake inspection of the books, accounts, records and documents of an intermediary in terms of sub-regulation (1) of regulation 17;
- (i) “principal officer” means any person who is responsible for the activities of an intermediary and includes—
 - (i) proprietor, in the case of a proprietary concern;
 - (ii) any partner, in the case of a partnership firm;
 - (iii) whole time/executive director/managing director, in the case of a body corporate;
 - (iv) trustee, in the case of a trust;
 - (v) any key employee; and
 - (vi) any person designated as a principal officer under the relevant regulations;
- (j) “relevant regulations” means any regulations made by the Board applicable to a class of intermediaries;
- (k) “securities laws” means the Act, the Securities Contract (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), and the rules and regulations made thereunder;
- (l) “schedule” means a schedule annexed to these regulations;
- (m) “self regulatory organization” means an organization of a class of intermediaries duly recognised by or registered with the Board and includes a stock exchange.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations shall have the meaning assigned thereto under the Act; or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or under the rules or regulations made thereunder.

CHAPTER II

REGISTRATION OF INTERMEDIARIES

Application for grant of certificate.

3. (1) On and from the commencement of these regulations, an application, for grant of a certificate to act as an intermediary, shall be made to the Board in Form A of Schedule I with such additional information as required to be provided under the relevant regulations, and the application fee, as specified in the relevant regulations:

Provided that the applicant seeking registration to act as a stock broker or sub-broker or a trading member or a clearing member or a depository participant shall make the application along with such additional information through the stock exchange or through the clearing corporation of which the applicant is a member or trading member or through the depository in which the applicant proposes to act as a participant, as the case may be:

Provided further that on and from the date specified by the Board by a notification in the Official Gazette, an application for registration to act as an intermediary as may be specified by the Board, shall be made to the relevant self-regulatory organization in Form A with such additional information and the application fee as specified in the relevant regulations.

(2) The stock exchange, the clearing corporation, the depository or the specified self-regulatory organization, as the case may be, shall examine the eligibility of the applicant in terms of these regulations, relevant regulations and the rules, regulations or bye-laws of the concerned stock exchange, clearing corporation, depository or the self regulatory organization and forward the application with the application fees to the Board along with its recommendation as early as possible but not later than thirty days of receipt of the complete application with the specified application fees.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), any application made by an intermediary prior to the commencement of these regulations in relation to such intermediary, containing such particulars or as near thereto as are specified in Form A and such additional information as required under the relevant regulations which is pending with the Board, shall be treated as an application made in pursuance of sub-regulation (1) and be dealt with accordingly.

(4) An intermediary, who was granted a certificate under the relevant regulations prior to the commencement of these regulations in relation to such intermediary, may continue to act as such, subject to the following,—

(a) where the certificate was granted for a specified period, an application for grant of certificate under sub-regulation (1) shall be made by the intermediary at least three months prior to the expiry of such period or three months prior to expiry of two years from the commencement of these regulations in relation to such intermediary, whichever is earlier and if the intermediary fails to do so, it shall cease to act as an intermediary on and from the expiry of the aforementioned period;

(b) where a certificate has been granted to an intermediary on a permanent basis, the certificate may continue to be valid under these regulations subject to the condition that the intermediary shall, within two years of commencement of these regulations in relation to such intermediary, furnish the information in Form A to the Board and upload the information in Part I thereof on the website specified by the Board:

Provided that the time specified in clause (b) may be extended by the Board up to a period of six months on sufficient reasons being shown by the intermediary.

(5) An intermediary who has complied with the provisions of clause (b) of sub-regulation (4), shall be deemed to have been granted certificate under these regulations, subject to the payment of fees specified under the relevant regulations.

(6) Subject to the provisions of the relevant regulations, an applicant or an intermediary as the case may be may carry on the activities of one or more intermediaries only if it obtains a separate certificate to carryon each such activity.

Disclosure of information.

4. (1) The information contained in Part I of Form A shall be disclosed to the public by uploading such information on the website as specified by the Board:

Provided that the other relevant information furnished by the intermediary in Part II of Form A which relates to commercial confidence and private information of the intermediary, may be treated as confidential by the Board.

(2) Any material change in the information furnished or uploaded under these regulations shall be updated by the intermediary promptly but not later than fifteen days of the occurrence of such change.

Furnishing of information and clarification.

5. (1) The Board may require the applicant to furnish further information or clarifications, regarding matters relevant to the activity of such an intermediary or which may otherwise be considered necessary by the Board, to consider and dispose of the application.

(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Board, within the

time specified in this regard by the Board.

Verification of information

6. (1) While considering the application, the information furnished by the applicant and its eligibility, the Board may, if it so desires, verify the information by physical verification of documents, office space, and inspect the availability of office space, infrastructure, and technological support which the applicant is required to have.

(2) For the purpose under sub-regulation (1), the Board may appoint any person including an auditor.

Consideration of application

7. (1) For considering the eligibility of the applicant and grant of certificate to such applicant, the Board shall take into account all matters which it deems relevant to the activities in the securities market, including but not limited to the following—

- (a) whether the applicant or any of its associates have in the past been refused certificate by the Board and if so, the ground for such refusal;
- (b) whether the applicant, its directors or partners, or trustees, as the case may be or its principal officer is involved in any pending litigation connected with the securities market which has an adverse bearing on the business of the applicant or on development or functioning of the securities markets;
- (c) whether the applicant satisfies the eligibility criteria and other requirements as specified in these regulations and the relevant regulations;
- (d) whether the grant of a certificate to the applicant is in the interest of the investors and the development of the securities market.

(2) Any application for grant of certificate :—

- (a) which is not complete in all respects and does not conform to the requirements in Form A and the requirements specified in the relevant regulation;
- (b) which does not contain such additional information as required by the Board;
- (c) which is incorrect, false or misleading in nature;
- (d) where the applicant is not in compliance with the eligibility requirements as set out under these regulations or the relevant regulations;
- (e) where the applicant is not a 'fit and proper person' as stated in Schedule II;
- (f) where the principal officer does not have the requisite qualification or experience as required under the relevant regulations;

shall be rejected by the Board for reasons to be recorded by the Board in writing.

(3) Before rejecting an application, the applicant shall be given an opportunity in writing to make good the deficiencies within the time specified by the Board, for the purpose :

Provided that where an application is rejected for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity may be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate under these regulations or any other regulations for a period of one year from the date of such rejection.

Procedure for grant of certificate

8. (1) The Board on being satisfied that the applicant is eligible, shall grant a certificate in the form specified in the relevant regulations and send an intimation to the applicant in this regard :

Provided that where a pending proceeding before the Board or any court or tribunal may result in the suspension or cancellation of the certificate, the Board may give a conditional registration.

(2) When an intermediary, who has been granted a certificate and who has filed Form A under these regulations, wishes to commence a new activity which requires a separate certificate under the relevant regulations, it shall, while seeking such certificate, not be required to file Form A, and shall furnish to the Board only such additional information as is required under the relevant regulations.

Conditions of certificate

9. (1) Any certificate granted by the Board to an intermediary shall be subject to the following conditions, namely:—

- (a) where the intermediary proposes to change its status or constitution, it shall obtain prior approval of the Board for continuing to act as an intermediary after such change in status or constitution;
- (b) it shall pay the applicable fees in accordance with the relevant regulations;
- (c) it shall abide by the provisions of the securities laws and the directions, guidelines and circulars as may be issued thereunder;
- (d) it shall continuously comply with the requirements of regulation 4;
- (e) it shall meet the eligibility criteria and other requirements specified in these regulations and the relevant regulations :

Provided that the Board may impose other conditions as it may deem fit in the interest of investors or orderly development of the securities market or for regulation of the working of the intermediary and the intermediary shall comply with such conditions.

(2) A request for prior approval, under clause (a) of sub-regulation (1) which is complete in all respects shall be disposed off by the Board within a period of sixty days

from the date of receipt of such request and where the decision of the Board has not been communicated to the intermediary within the said period of sixty days, the prior approval shall be deemed to have been granted.

(3) The request for prior approval under clause (a) of sub-regulation (1) shall contain the information in Form A in respect of the intermediary after the proposed change in status or constitution and the information under Part I of Form A shall be uploaded in the website specified by the Board.

Effect of refusal to grant certificate or expiry of certificate

10. (1) Where an intermediary has failed to make an application under sub-regulation (4) of regulation 3 or where an existing intermediary has been refused grant of certificate under these regulations, the intermediary shall:—

- (a) forthwith cease to act as such intermediary;
- (b) transfer its activities to another intermediary which has been granted a certificate for carrying on such activity and allow its clients or investors to withdraw or transfer their securities or funds held in its custody without any additional cost to such client or investor;
- (c) make provisions as regards liability incurred or assumed by the intermediary;
- (d) take such other action, within the time period and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Board.

(2) While refusing grant of certificate under these regulations to an intermediary, the Board may impose such conditions upon the intermediary as it deems fit for protection of investors or clients of the intermediary or the securities market and such conditions shall be complied with.

Period of validity of certificate

11. Subject to compliance with the provisions of the Act, these regulations and the relevant regulations, the certificate granted to an intermediary shall be permanent unless surrendered by the intermediary or suspended or cancelled in accordance with these regulations.

CHAPTER III

GENERAL OBLIGATIONS OF INTERMEDIARIES

General obligations

12. (1) An intermediary shall provide the Board with a certificate of its compliance officer on the 1st April of each year certifying :

- (a) the compliance by the intermediary with all the obligations, responsibilities and the fulfillment of the eligibility criteria on a continuous basis under these regulations and the relevant regulations;
- (b) that all disclosures made in Form A and under the relevant regulations are true and complete.

(2) Each intermediary shall prominently display a photocopy of the certificate at all its offices including branch offices.

(3) The intermediary shall also prominently display the name and contact details of the compliance officer to whom complaint may be made in the event of any investor grievance.

(4) The intermediary shall maintain such books, accounts and records as specified in the relevant regulations.

Redressal of investor grievances

13. (1) The intermediary shall make endeavours to redress investor grievances promptly but not later than forty-five days of receipt thereof and when called upon by the Board to do so it shall redress the grievances of investors within the time specified by the Board.

(2) The intermediary shall maintain records regarding investor grievances received by it and redressal of such grievances.

(3) The intermediary shall at the end of each quarter of a Financial Year ending on 31st March upload information about the number of investor grievances received, redressed and those remaining unresolved beyond three months of the receipt thereof by the intermediary on the website specified by the Board.

Appointment of compliance officer

14. (1) An intermediary shall appoint a compliance officer for monitoring the compliance by it of the requirements of the Act, rules, regulations, notifications, guidelines, circulars and orders made or issued by the Board or the Central Government, or the rules, regulations and bye-laws of the concerned stock exchanges, or the self-regulatory organization, where applicable :

Provided that the intermediary may not appoint compliance officer if it is not carrying on the activity of the intermediary.

(2) The compliance officer shall report to the intermediary or its board of directors, in writing, of any material non-compliance by the intermediary.

Investment advice

15. (1) An intermediary, its directors, officers, employees or key management personnel shall not render, directly or indirectly, any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, unless a disclosure of its interest, direct or indirect, including its long or short position in the said security has been made, while rendering such advice.

(2) If an intermediary's directors, officers, employees or key management personnel are rendering such advice, the intermediary shall ensure that while rendering such advice he discloses his interest, the interest of his dependent family members and that of the employer including employer's long or short position in the said security.

(3) An intermediary shall not make a recommendation to any client or investor who may be expected to rely thereon to acquire, dispose of or retain any securities unless he has reasonable grounds to believe that the recommendation is suitable.

Code of conduct.

16. An intermediary and its directors, officers, employees and key management personnel shall continuously abide by the code of conduct specified in Schedule III.

CHAPTER-IV

INSPECTION AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS

Right of inspection by the Board.

17. (1) Without prejudice to the provisions of section 11 and section 11C of the Act, the Board may appoint one or more persons as inspecting authority to undertake the inspection of the books, accounts, records including telephone records and electronic records and documents of an intermediary for any purpose, including the purposes as specified under sub-regulation (2).

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include:

- (a) to ensure that the books of account, records including telephone records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under the relevant regulations;
- (b) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the intermediary to fulfill its obligations under the relevant regulations;
- (c) to ascertain whether any circumstances exist which would render the intermediary unfit or ineligible;
- (d) to ascertain whether the provisions of the securities laws and the directions or circulars issued thereunder are being complied with;
- (e) to inquire into the complaints received from investors, clients, other market participants or any other person on any matter having a bearing on the activities of the intermediary;
- (f) to inquire suo motu into such matters as may be deemed fit in the interest of investors or the securities market.

Notice before inspection.

18. (1) Before undertaking an inspection under regulation 17, the inspecting authority shall give a notice to the concerned intermediary:

Provided that where the inspecting authority is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with such notice.

(2) During the course of inspection, the intermediary shall be bound to discharge its obligations provided under regulation 19.

Obligations of Intermediary on inspection.

19. (1) It shall be the duty of every director, proprietor, partner, trustee, officer, employee and any agent of an intermediary which is being inspected, to produce to the inspecting authority such books, accounts, records including telephone records and electronic records and documents in his custody or control and furnish to the inspecting authority with such statements and information relating to its activities within such time as the inspecting authority may require.

(2) The intermediary shall allow the inspecting authority to have reasonable access to the premises occupied by such intermediary or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records including telephone records and electronic records and documents in the possession of the intermediary or any such other person and also provide copies of documents or other material which in the opinion of the inspecting authority are relevant for the purposes of the inspection.

(3) Without prejudice to the provisions of sub-section (3) of section 11 of the Act, the inspecting authority shall, in the course of inspection, be entitled to examine or record statements of any principal officer, director, trustee, partner, proprietor or employee of such intermediary.

(4) It shall be the duty of every director, proprietor, trustee, partner, officer and employee of such intermediary to give to the inspecting authority all assistance which the inspecting authority may reasonably require in connection with the inspection.

Appointment of auditor or valuer.

20. (1) The Board may appoint a qualified auditor to inspect the books of account or the affairs of an intermediary:

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting authority mentioned in regulation 17 and the obligation of the intermediary and its employees mentioned in regulation 19 shall be applicable to the inspection under this regulation.

Explanation: For the purpose of this sub-regulation, the expression 'qualified auditor' shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(2) The Board may appoint a qualified valuer or direct a qualified valuer to be appointed by the intermediary, if so considered necessary by the Board.

(3) The expenses of such audit under sub-regulation (1) or valuation under sub-regulation (2) shall be borne by the intermediary.

Submission of report to the Board.

21. (1) The inspecting authority shall submit an inspection report including interim reports to the Board.

(2) On submission of the inspection report, the Board may take such action thereon as it may deem fit and appropriate.

CHAPTER-V

ACTION IN CASE OF DEFAULT AND MANNER OF SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE

Definitions

22. In this Chapter unless the context otherwise requires,—

- (a) “date of receipt of reply” includes the date on which the noticee makes oral submissions, if any;
- (b) “designated authority” means an officer of the Board and includes a bench of such officers appointed under regulation 24;
- (c) “designated member” means the Chairman or a Whole Time Member of the Board designated for the purpose;
- (d) “noticee” means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

Cancellation or suspension of registration and other actions

23. Where any person who has been granted a certificate of registration under the Act or regulations made thereunder,—

- (a) fails to comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted to him;
- (b) contravenes any of the provisions of the securities laws or directions, instructions or circulars issued thereunder; the Board may, without prejudice to any action under the securities laws or directions, instructions or circulars issued thereunder, by order take such action in the manner provided under these regulations.

Appointment of designated authority

24. (1) Where it appears to the designated member, that any person who has been granted certificate of registration under the Act, regulations made thereunder has committed any default of the nature specified in regulation 23, he may appoint an officer not below the rank of a Division Chief, as a designated authority:

Provided that the designated member may, at his discretion, appoint a bench of three officers, each of whom shall not be below the rank of a Division Chief:

Provided further that such bench shall be presided by the seniormost amongst them and all the decisions or recommendations of such bench shall be by way of majority.

(2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

Issuance of notice.

25. (1) The designated authority shall, if it finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the concerned person requiring him to show cause as to why the certificate of registration granted to it, should not be suspended or cancelled or why any other action provided herein should not be taken.

(2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, rules, regulations, circulars or guidelines in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection, if any, carried out.

(4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation along with documentary evidence, if any, in support of the representation to the designated authority.

Reply by the noticee.

26. (1) The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons in writing.

(2) If the noticee does not reply to the show cause notice, the designated authority may proceed with the matter ex-parte recording the reasons for doing so and make recommendation as the case may be on the basis of material facts available before it.

Action in case of default.

27. After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of law or directions, instructions or circulars administered by the Board the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending,—

- (i) suspension of certificate of registration for a specified period;
- (ii) cancellation of certificate of registration;
- (iii) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch a new scheme for the period specified in the order;
- (iv) debarring a principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary or other registered person for the period specified in the order;

- (v) debarring a branch or an office of the noticee from carrying out activities for the specified period;
- (vi) warning the noticee.

Procedure for action on receipt of the recommendation

28. (1) On receipt of the report recommending the measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, as the designated member considers appropriate, should not be taken.

(2) The noticee may, within twenty one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the noticee and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavour shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.

Common order

29. The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.

Intimation of the order

30. (1) Every report made by a designated authority and every order passed by the designated member under this Chapter shall be dated and signed.

(2) A copy of the order passed under this Chapter shall be sent to the noticee and also uploaded on the website of the Board.

(3) If the noticee is a member of a stock exchange, clearing corporation, a depository or a self-regulatory organization, a copy of the order shall also be sent to the concerned stock exchange, clearing corporation, depository or self regulatory organization.

Surrender of any certificate of registration.

31. (1) Any person, who has been granted a certificate of registration under the Act or the regulations made thereunder, desirous of giving up its activity and surrender the certificate, may make a request for such surrender to the Board and while disposing such request, the Board shall not be bound by the procedure specified in the foregoing provisions of this Chapter.

(2) While disposing a request under this regulation, the Board may require the concerned person to satisfy the Board the factors as it deems fit, including but not limited to the following—

- (a) the arrangements made by the person for maintenance and preservation of records

and other documents required to be maintained under the relevant regulations;

- (b) redressal of investor grievances;
- (c) transfer of records, funds or securities of its clients;
- (d) the arrangements made by it for ensuring continuity of service to the clients;
- (e) defaults or pending action, if any.

(3) While accepting surrender, the Board may impose such conditions upon the person as it deems fit for protection of the investors or its clients or the securities market and such person shall comply with such conditions.

Effect of debarment, suspension, cancellation or surrender

32. (1) On and from the date of debarment or suspension of the certificate, the concerned person shall—

- (a) not undertake any new assignment or contract or launch any new scheme and during the period of such debarment or suspension it shall cease to carryon any activity in respect of which certificate had been granted;
- (b) allow its clients or investors to withdraw or transfer their securities or funds held in its custody or withdraw any assignment given to it, without any additional cost to such client or investor;
- (c) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
- (d) take such other action including the action relating to any records or documents and securities or money of the investors that may be in custody or control of such person, within the time period and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Board while passing order under this Chapter or otherwise.

(2) On and from the date of surrender or cancellation of the certificate, the concerned person shall—

- (a) return the certificate of registration so cancelled to the Board and shall not represent itself to be a holder of certificate for carrying out the activity for which such certificate had been granted;
- (b) cease to carry on any activity in respect of which the certificate had been granted;
- (c) transfer its activities to another person holding a valid certificate of registration to carry on such activity and allow its clients or investors to withdraw or transfer their securities or funds held in its custody or to withdraw any assignment given to it, without any additional cost to such client or investor;

- (d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
- (e) take such other action including the action relating to any records or documents and securities or money of the investors that may be in custody or control of such person, within the time period and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Board while passing order under this Chapter or otherwise.

Appeal to Securities Appellate Tribunal

33. The person aggrieved by an order under these regulations may prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal against such order in accordance with the provisions of Section 15T of the Act and Rules prescribed in this regards.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Manner of service of notice and order and publication of order

34. (1) Any notice issued or order passed under these regulations may be served—

- (a) by hand delivery to the concerned person or his duly authorized agent; or
- (b) by delivery, at the address available on the records of the Board and addressed to that person or his duly authorized agent, by registered post acknowledgement due or by speed post or by such courier service or by electronic mail service or by any other means of transmission which affords a record of delivery; or
- (c) in case of a stock broker or a sub-broker or a depository participant through the concerned stock exchange or the depository respectively; and
- (d) if it cannot be served as per clause (a) or (b) or (c), by affixing the same on the door or some other conspicuous part of the premises in which such person resides or is known to have last resided or carries on business or is known to have last carried on business or personally works for gain or is known to have last personally worked for gain.

(2) Every order passed under these regulations shall be put on the website of the Board.

Directions

35. Without prejudice to any order under the securities laws and the directions, guidelines and circulars as may be issued thereunder including an order under Chapter V of these regulations the Board may in the interest of the securities market, in the interest of the investors or for the purpose of securing the proper management of

any intermediary, issue, necessary direction including but not limited to any or all of the following—

- (a) directing the intermediary or other persons associated with securities market to refund any money or securities collected from the investors under any scheme or otherwise, with or without interest;
- (b) directing the intermediary or other persons associated with securities market not to access the capital market or not to deal in securities for a particular period or not to associate with any intermediary or with any capital market related activity;
- (c) directing the recognised stock exchange concerned not to permit trading in the securities or units issued by a mutual fund or collective investment scheme;
- (d) directing the recognised stock exchange concerned to suspend trading in the securities or units issued by a mutual fund or collective investment scheme;
- (e) any other direction which the Board may deem fit and proper in the circumstances of the case:

Provided that before issuing any directions the Board shall give a reasonable opportunity of being heard to the persons concerned :

Provided further that if the circumstances warrant any interim direction is required to be passed immediately, the Board shall give a reasonable opportunity of hearing to the persons concerned after passing the direction, without any undue delay.

Power of the Board to issue clarifications

36. In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Board may issue clarifications and guidelines in the form of circulars.

Amendments to other regulations

37. The regulations specified in the Schedule IV shall be amended in the manner and to the extent stated therein.

Repeal and saving

38. (1) With effect from publication of these regulations in the Official Gazette—

- (a) the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and imposing Penalty) Regulations, 2002; and
- (b) the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Persons) Regulations, 2004.

shall be repealed

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under those regulations including an

enquiry commenced or notice issued under the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and imposing Penalty) Regulations, 2002, before the publication of these regulations in the Official Gazette, shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.

(3) After the repeal of the regulations referred to in sub-regulation (1), any reference thereto in any regulation, guidelines, circulars shall be deemed to be a reference to Chapter V and Schedule II, respectively.

SCHEDULE I

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) REGULATIONS, 2008

[Regulation 3]

FORM A

Application for grant of certificate

The information contained herein is updated as on :
dd/mm/yy

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP FORM

1. Applicants must submit to the Board a completed application form together with appropriate supporting documents and applicable application fees. Supporting documents should be attested as true by a notary public.

2. This application form should be filled in accordance with the regulations.

3. Application for registration will be considered, only if it is complete in all respects.

4. All answers must be typed.

5. Information which needs to be supplied in more detail may be given on separate sheets which should be attached to the application form.

6. All signatures on the application must be original.

7. Every page of the form as well as every additional sheet must be initialed by the authorised signatory of the applicant.

Part I

1. General details of the applicant and its affiliates : Management Compliance Matrix/Structure

1.1. Name of the applicant :

1.2. Address of the registered office, address for correspondence, telephone numbers, fax numbers, e-mail, website, name and telephone number of the contact person, address of branch office, if any :

1.3. Date and place of incorporation/establishment and registration number given by the Registrar of Companies or any other authority :

1.4. Legal status of the applicant and the law, under which it is incorporated, established or registered, if any including where the applicant is a listed entity, the details of the exchanges (whether in India or abroad) where the applicant is listed :

1.5. Brief description of the principal activity of the applicant : (alongwith copies of the constitutional documents of the applicant) :

1.6. Year of commencement of such activities (if applicable) :

1.7. Shareholding pattern of the applicant (please set out the names of all such persons who hold whether directly or indirectly more than 5% of the shareholding or voting rights in the company) :

Name of the shareholder	No. of Shares	[% of shareholding] / [% of voting rights]
-------------------------	---------------	--

Where control over the applicant is exercised by a person by way of an agreement or arrangement, details and documentation in relation to such agreement or arrangement as the case may be.

1.8. Details of significant affiliates of the applicant operating in India or abroad and activities carried out by them including details as regards the legal status of each such affiliates and the law, under which it is incorporated, established or registered, if any :

Legal Status and details of registration

Name _____

Address _____

Telephone no. _____

Fax No. _____

E-mail address _____

Nature of interest of the applicant in the affiliate, if any _____

Nature of interest of such affiliate in the applicant, if any _____

1.9. Details of registration/recognition of the applicant with the Board and with other regulatory authorities or with stock exchanges or self regulatory organization (whether in India or abroad) :

The Regulator	Details of registration	Registration No.	Period of validity
SRO			

1.10. Details of registration/recognition of each affiliates of the applicant with the Board or with other regulatory authorities or with stock exchanges or self regulatory organizations (whether in India or abroad) :

The Regulator	Details of registration	Registration No.	Period of validity
SRO			

1.11 Details of the Compliance Officer :

Name	
Job Title	
Business	
Address	
Telephone No.	
Fax No.	
E-mail address	

1.12 Details of principal officers :

Name Of Person	Responsibility	Qualification/Experience

1.13 Details of the Key Management Personnel

Name of Person	Responsibility	Qualification/Experience

1.14 Details of any conviction or any declaration of insolvency/winding-up of the applicant.

1.15 Details of actions taken against the applicant or its associates by any regulatory authorities.

Sr. No.	Authority	Description of alleged default	Action taken	Current status

Explanation: For the purpose of this clause 'affiliate' shall mean where the applicant is a company, its holding company and its subsidiaries and where the applicant is an individual his/her dependant relatives.

2. Details of arbitration/litigation which could have a material adverse effect on the functioning of the intermediary and investor complaints.

2.1 Complaints pending for over three months:

Sr. No. of the complainant	Name of the complainant	Date of receipt of complaint	Short description of complaint	Current status

2.2 Arbitration/litigation cases :

Forum	Name of the Petitioner	Short description of issue	Current stage of proceeding	Details of interim orders	Details of final award/awards passed	Details of final order

3. Brief description of the group :

3.1 Brief description of the group, if any, to which the applicant belongs. Please confirm the details of the

company and the group, tracing them down to the individual persons in control.

4. Management Details :

4.1 Provide the following details of the directors/partners/trustees of the applicant as the case may be:

Name	
Details of interest in the applicant	
Directorships in other entities	

Controlling interest in other entities	
4.2 Names of Promoters of the Applicant should be provided.	

Part II**5. Financial Reporting and Disclosure (where the intermediary is active):**

5.1 Audited balance sheets and profit and loss account statements for the past three years (including notes to accounts);

5.2 Net Worth of the applicant for the past three years; segment wise turnover of the applicant (where necessary) (for e.g. where the applicant is a stock broker, then the segment wise turnover i.e. turnover under the cash segment, the derivative segment, the commodities segment etc. may be provided).

6. Details of the taxation authority :

6.1 Please provide details of the authority where the applicant is subject to taxation.

6.2 Permanent Account Number/Registration Number/Code given by tax authority (if any) of the applicant and its directors, as applicable :

7. Details of promoters and management personnel :

7.1 Provide address and contact details (including telephone numbers, email, fax etc.) of the applicant's promoters as specified in Clause 4.2 of Part I of the Form.

7.2 Provide details of address and contact details (including telephone numbers, email, fax etc.) of the applicant's management personnel as specified in Clause 4.1 of Part I of the Form.

7.3 Provide Director's Identification Number of the directors of the applicant.

8. Details of any show cause notices received by the applicant from any regulatory authority.

Sr. No.	Date of Notice	Details of alleged violation	Current status

9. Undertaking and Declarations :

We hereby represent, warrant and declare that :

1. The information supplied in the application, including the attachment sheets thereto, is complete, true and accurate in all respects;

2. We are in compliance with, and have adhered to and fulfilled, all the criteria and conditions applicable for grant of certificate;

3. We further undertake that we will immediately notify the Securities and Exchange Board of India of any change in the information provided in the application in the manner as set out under the regulations;

4. We further undertake that we shall comply with the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the rules, regulations, guidelines, notifications, circulars, and any other directions as may be passed by the Securities and Exchange Board of India from time to time, issued thereunder and applicable to us, and all other relevant laws including guidelines issued by the Reserve Bank of India and the Government of India.

5. We further undertake that as a condition of grant of certificate, we shall abide by such operational instructions/directives as may be issued by Securities and Exchange Board of India from time to time under provisions of the Act or any other law for the time being in force.

For and on behalf of (Name of the applicant)

Name of the applicant

Signature

Name of signatory

Position

Date dd/mm/yyyy

Notes:

SCHEDULE II

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) REGULATIONS, 2008

(See regulation 7)

Criteria for determining a 'fit and proper person'

For the purpose of determining as to whether an applicant or the intermediary is a 'fit and proper person' the Board may take account of any consideration as it deems fit, including but not limited to the following criteria in relation to the applicant or the intermediary, the principal officer and the key management persons by whatever name called—

- (a) integrity, reputation and character;
- (b) absence of convictions and restraint orders;
- (c) competence including financial solvency and networth.

SCHEDULE III

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INTERMEDIARIES) REGULATIONS, 2008

[See regulation 16]

CODE OF CONDUCT

I INVESTOR PROTECTION

1.1 Investors/Clients

Every intermediary shall make all efforts to protect the interests of investors and shall render the best possible advice to its clients having regard to the client's needs and the environments and his own professional skills.

1.2 High Standards of Service

An intermediary shall ensure that it and its key management personnel, employees, contractors and agents, shall in the conduct of their business, observe high standards of integrity, dignity, fairness, ethics and professionalism and all professional dealings shall be affected in a prompt, effective and efficient manner.

An intermediary shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect to the conduct of its business.

1.3 Exercise of Due Diligence and no Collusion

An intermediary shall at all times render high standards of service, exercise due skill and diligence over persons employed or appointed by it, ensure proper care and exercise independent professional judgment and shall not at any time act in collusion with other intermediaries in a manner that is detrimental to the investor(s).

1.4 Fees

An intermediary shall not increase charges/fees for the services rendered without proper advance notice to its clients/investors.

II DISBURSAL OF AMOUNTS

2.1 . Disbursal of Amounts

An intermediary shall be prompt in disbursing dividends, interests or any such accrual income received or collected by it on behalf of its clients/investors.

III DISBURSAL OF INFORMATION

3.1 An intermediary shall ensure that adequate disclosures are made to the clients/investors in a comprehensible and timely manner so as to enable them to make a balanced and informed decision.

3.2 An intermediary shall not make any misrepresentation and ensure that the information provided to the clients/investors is not misleading.

3.3 An intermediary shall not make any exaggerated statement whether oral or written to the client/investor, either about its qualification or capability to render certain services or its achievements in regard to services rendered to other clients/investors.

3.4 An intermediary shall not divulge to anybody, either orally or in writing, directly or indirectly, any

confidential information about its clients/investors, which has come to its knowledge, without taking prior permission of its clients/investors except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.

IV. CONFLICT OF INTEREST

4.1 An intermediary shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of his interest and shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner. An intermediary shall make appropriate disclosure to the client/investor of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as an intermediary which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

4.2 An Intermediary or any of its directors, or employee having the management of the whole or substantially the whole of affairs of the business, or an associate of the intermediary shall not, either through its account or their respective accounts or through their family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

V. COMPLIANCE AND CORPORATE GOVERNANCE

5.1 An Intermediary shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place. It shall not engage in fraudulent and manipulative transactions in the securities listed on any stock exchange in India and shall not indulge in any unfair competition (including resorting to unfair means for inducing another intermediaries' clients) which is likely to harm the interests of other intermediaries or investors or is likely to place such other intermediaries in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.

5.2 An Intermediary shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.

5.3. An Intermediary shall not be a party to or instrumental in or indulge in—

- (a) creation of false market for securities listed or proposed to be listed on any stock exchange in India;
- (b) price rigging or manipulation of prices of securities listed or proposed to be listed on any stock exchange in India; or
- (c) passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed or proposed to be listed on any stock exchange to any person or intermediary, or
- (d) any activity for distorting market equilibrium or which may affect the smooth functioning of the market or for personal gain.

5.4 An Intermediary shall co-operate with the Board, or any authority designated by the Board, as and when required and shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Board or neglect or fail or refuse to submit to the Board or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence and papers or any part thereof as may be demanded/requested from time to time.

5.5 An Intermediary shall ensure that any change in registration status/any penal action taken by Board or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients/investors is promptly informed to the clients/investors and any business remaining outstanding is transferred to another registered person in accordance with any instructions of the affected clients/investors or as per the instructions of the Board and the provisions of the relevant regulations.

5.6 An Intermediary shall maintain an appropriate level of knowledge and competency and abide by the provisions of any act, regulations, circulars and guidelines of the Central Government, the Reserve Bank of India, the Board, the stock exchange or any other applicable statutory or self regulatory or other body, as the case may be, and as may be applicable to the Intermediary in respect of the business carried on by such Intermediary. An Intermediary shall also comply with the award of the Ombudsman passed under the Securities and Exchange Board of India (Ombudsman) Regulations, 2003.

5.7 An Intermediary shall ensure that the Board is promptly informed about any action, legal proceedings, etc., initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, and directions of the Board or of any other regulatory body.

VI. INTERMEDIARY INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS

6.1 An Intermediary shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its clients, investors and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

6.2 An Intermediary also registered with the Board in any other capacity/category shall endeavour to ensure that arms length relationship is maintained in terms of both manpower and infrastructure between the activities carried out as an Intermediary and other permitted activities.

6.3 An Intermediary shall establish and maintain adequate infrastructural facility to be able to discharge its services as such intermediary to the satisfaction of clients/investors, and the operating procedures and systems of the intermediaries shall be well documented and backed by operations manuals.

6.4 An Intermediary shall create and maintain the records of all documents and data in their custody in such manner that the tracing of such document or data is

facilitated in the event of loss of original records or documents for any reason.

SCHEDULE IV
**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
 (INTERMEDIARIES) REGULATIONS, 2008**

[See regulation 37]

Amendments to other regulations

1. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Bankers to an Issue) Regulations, 1994.

- (i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the banker to an issue is a fit and proper person, the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 22, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2000” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

- (iii) For regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Liability for action in case of default

23. A banker to issue who contravenes any of the provisions of the Act, Rules or Regulations framed thereunder shall be liable for one or more actions specified therein including the action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

2. Amendment of Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999.

- (i) For regulation 9A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

9A. For the purpose of determining whether an applicant or the collective investment management company is a fit and proper person, the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 56, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

- (iii) In regulation 59, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

3. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999.

- (i) For regulation 5A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

5A. For the purpose of determining whether an applicant or the credit rating agency is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 33, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

- (iii) For regulation 34, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Liability for action in case of default

34. A credit rating agency which contravenes any of the provisions of the Act, Rules or Regulations framed thereunder shall be liable for one or more actions specified therein including the action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

4. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Custodian of Securities) Regulations, 1996.

- (i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the custodian of securities is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 25, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

- (iii) In regulation 26, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

5. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Debenture Trustees) Regulations, 1993.

- (i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the debenture trustee is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 23, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

- (iii) In regulation 25, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

6. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Depositories and Participants) Regulations, 1996.

- (i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the depository and participant is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 63, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

- (iii) In regulation 64, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board

of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

7. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Foreign Institutional Investors) Regulations, 1995.

- (i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the foreign institutional investor is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) For regulation 21, the following regulation shall be substituted, namely:—

“Liability for action in case of default

21. A foreign institutional investor who contravenes any of the provisions of the Act, Rules or Regulations framed thereunder shall be liable for one or more actions specified therein including the action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

8. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000.

- (i) For regulation 4A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“Criteria for fit and proper person

4A. For the purpose of determining whether an applicant or the foreign venture capital investor is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 23, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

9. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

- (i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely:—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the merchant banker is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

(ii) In regulation 33, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

(iii) For regulation 35, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Liability for action in case of default

35. A merchant banker who contravenes any of the provisions of the Act, Rules or Regulations framed thereunder shall be liable for one or more actions specified therein including the action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

10. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Mutual Funds) Regulations, 1996.

(i) For regulation 7 A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

7 A. For the purpose of determining whether an applicant or the mutual fund is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

(ii) In regulation 65, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

(iii) In regulation 68, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

11. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Portfolio Managers) Regulations, 1993.

(i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the portfolio manager is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

(ii) In regulation 28, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for

Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

(iii) For regulation 30, the following regulations shall be substituted, namely :—

“Liability for action in case of default

30. A portfolio manager who contravenes any of the provisions of the Act, Rules or Regulations framed thereunder shall be liable for one or more actions specified therein including the action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

12. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.

(i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

6A. For the purpose of determining whether an applicant or the registrar to an issue and share transfer agent is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

(ii) In regulation 20, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

(iii) In regulation 22, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

13. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Stock Brokers and Sub Brokers) Regulations, 1992.

(i) For regulation 5A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

5A. For the purpose of determining whether an applicant or the stock broker, sub-broker, trading member and clearing member is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 23, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries), Regulations, 2008” shall be substituted.
- (iii) In sub-regulation (ii) of regulation 25, for the words “the Securities and Exchange, Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.
- (iv) In regulation 27, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

14. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Underwriters) Regulations, 1993.

- (i) For regulation 6A, the following regulation shall be substituted, namely :—
“Criteria for fit and proper person
- 6A. For the purpose of determining whether an applicant or the underwriter is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”
- (ii) In regulation 23, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for

Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

- (iii) For regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Liability for action in case of default

25. An underwriter who contravenes any of the provisions of the Act, Rules or Regulations framed thereunder shall be liable for one or more actions specified therein including the action under Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

15. Amendment of Securities and Exchange Board of India, (Venture Capital Funds) Regulations, 1996.

- (i) For regulation 4A, the following regulation shall be substituted, namely :—

“Criteria for fit and proper person

4A. For the purpose of determining whether an applicant or the venture capital fund is a fit and proper person the Board may take into account the criteria specified in Schedule II of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008.”

- (ii) In regulation 30, for the words “the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” the words “Chapter V of the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be substituted.

C. B. BHAVE, Chairman
[ADVT III/IV/69 ZB/2008/Exty.]